

STATIC GK QUESTIONS SET – 15

1.Which is Satyajit Ray's famous film about the decline of the aristocratic zamindari style of living?/सत्यजीत रे की कौन की प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? - Jalsaghar/जलसाघर

Jalsaghar is a film directed by Satyajit Ray that deals with the decline of the aristocratic zamindari style. He was awarded the Dadasaheb Phalke Award in 1985. Shortly before his death, he was awarded the Bharat Ratna, India's highest honor. Pather Panchali, Apur Sansar, Charulata are her other famous movies./जलसाघर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदारी शैली के पतन से संबंधित है। इन्हें 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु से कुछ समय पहले इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाथेर पांचाली, अपुर संसार, चारुलता इनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्में हैं

2.Where was the First experimental satellite telecommunication earth station set up in 1967 in India/भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? - Ahmedabad/अहमदाबाद

The first 'Experimental Satellite Communication Earth Station (ESCES)' was commissioned in 1967 in Ahmedabad, and also served as a training facility for Indian and international scientists and engineers./पहला 'प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन (ESCES)' 1967 में अहमदाबाद में चालू किया गया था, और इसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में भी काम किया।

3. Southernmost point of India?/ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? - Indira Point/ इंदिरा पॉइंट

The southernmost part of India is the Indira Point is located in the island of Andaman and Nicobar. It is a village in the Nicobar district at Great Nicobar Island of Andaman and Nicobar Islands in India.

भारत का सबसे दक्षिणी भाग अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। यह भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में निकोबार जिले का एक गाँव है।

4.How many organization are a part of the United Nations in India? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? - 26

The United Nations Organization is an international organization whose It was established in the year 1945. of this organization at the present time. The member strength is 193. At present there are 26 organizations of the United Nations operating in India. Some of the

major UN organizations in India are FAO ILO IMF UNDP UNHCR UNICEF or Women, WHO./संयुक्त राष्ट्र संघ एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। वर्तमान समय में इस संगठन की सदस्य संख्या 193 है। वर्तमान में भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के 26 संगठन कार्यरत हैं। भारत में कुछ प्रमुख यूएन संगठन एफएओ आइएलओ आईएमएफ यूएनडीपी यूएनएचसीआर यूनिसेफ यएन वुमेन, डब्ल्यू एचओ।

5. The movement for a separate Andhra was called/एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? - Visalandhra movement/विशालांध्र आन्दोलन

The Vishalandhra movement was a movement for a united state, Greater Andhra for all Telugu speaking people in post-independence India. The movement was led by the Communist Party of India under the banner of the Andhra Pradesh Mahasabha, demanding the merger of all Telugu-speaking regions into a single state. The movement was successful and under the States Reorganization Act, the state of Andhra Pradesh was formed on 1 November 1956 by merging the Telugu speaking areas of Hyderabad (Telangana) with Andhra Pradesh./विशालांध्र आंदोलन स्वतंत्रता के बाद भारत में सभी तेलुगु भाषियों के लिए एक संयुक्त राज्य, ग्रेटर आंध्र के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आंध्र प्रदेश महासभा के बैनर तले किया, जिसमें सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को एक राज्य में मिलाने की मांग की गई थी। आंदोलन सफल रहा और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर, 1956 को आंध्र प्रदेश के साथ हैदराबाद (तेलंगाना) के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्रप्रदेश राज्य का गठन हुआ।

6. Who was the Raja of Burdwan when Permanent Settlement was imposed स्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? - Tejchand/तेजचंद

Governor General Ward Cornwallis (1786-1793) implemented the Permanent Settlement, at that time the Raja of Vardhaman was Maharajadhiraj Bahadur Tej Chand Rai. Tej Chand Rai was only 6 years old at the time of death of his father Maharajadhiraj Bahadur Tilak Chand Rai in 1770. Therefore his mother Maharani Vishta Kumari took over the kingdom with the help of Diwan Roop Narayan Chaudhary. Tej Chand Rai himself took over the state from 1779. Therefore, he managed the Permanent Settlement System to improve the rent system. It is also called isthmari system. In this the zamindars were made permanent owners of the land. His right over the land was paternal and transferable. Land rights were taken away from the farmers. This system is in Bengal, Bihar, Orissa, North Karnataka and Implemented in Banaras block of Uttar Pradesh./गवर्नर जनरल वार्ड

कार्नेवालिस (1786-1793) ने स्थाई बंदोबस्त लागू किया, उस समय वर्धमान के राजा महाराजाधिराज बहादुर तेज चंद राय थे। 1770 में पिता महाराजाधिराज बहादुर तिलक चंद राय की मृत्यु के समय तेज चंदराय उम्र सिर्फ 6 वर्ष थी। इसलिए उनकी माता महारानी विष्ट कुमारी ने दीवान रूप नारायण चौधरी की मदद से राज्य को संभाला। 1779 से तेज चंद राय ने स्वयं ही राज्य को संभाल लिया 1786 में जब लार्ड कार्नेवालिस गवर्नर-जनरल बनकर भारत आया उस समय कम्पनी की राजस्व व्यवस्था अस्त-व्यस्त थी। अतः उसने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए स्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रबंधन किया। इसे इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक एवं हस्तांतरणीय था। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा ! उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखण्ड में लागू की गई।

7. When was India's hundredth space mission launched?/भारत का सौवां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? -September, 2012/सितम्बर, 2012

India successfully launched the hundredth space mission in September 2012 with PSLV-C21 from Sri Harikota. Currently in the 53rd flight of PSLV, PSLVICS1 rocket from Sri Harikota was launched on 28 February 2021 along with Brazilian satellite Amazonia-1 along with 18 other satellites./भारत ने सौवां अंतरिक्ष मिशन सितम्बर, 2012 में श्री हरिकोटा से PSLV-C21 के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वर्तमान में PSLV की 53वीं उड़ान में श्री हरिकोटा से PSLVICS1 राकेट से 28 फरवरी, 2021 को ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया-1 के साथ 18 अन्य उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया।

8. The Rourkela Steel Plant started with the inauguration of first blast furnace by the then President of India in/..... में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन का राउरकेला स्टील प्लांट का सुभारम्भ किया गया। -1959

Rourkela Steel Plant is located in the north-west end of Orissa in a rich mineral area. This is the first integrated steel plant in the public sector in India, which was established with the cooperation of Germany. On 3 February 1959, the then President Dr. Rajendra Prasad inaugurated the first blast furnace of Rourkela Steel Plant (Jalstafurnace) 'Parvati'./ राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा के उत्तर-पश्चिम छोर पर समृद्ध खनिज क्षेत्र में स्थित है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है, जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया

था। 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र की पहली वाट्या भट्टी जलास्टफर्नेस) 'पार्वती' का उद्घाटन किया।

9. The oldest Nuclear research reactor of India? भारत का सबसे पुरान नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? - Kamini/कामिनी

Apsara is the oldest nuclear research reactor in India. It was established in the year 1956 in the Trombay campus of Bhabha Atomic Research Centre./भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। इसे वर्ष 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्राम्बे परिसर में स्थापित किया गया था।

Kamini is a research reactor. Which was specially designed to make Uranium-233 fuel unusable./कामिनी अनुसंधान रिएक्टर है। जिसे विशेष रूप से यूरेनियम- 233 ईंधन अउपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था।

10. Spring tiger is a biography of /स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है?- Subhash Chandra Bose/शुभाष चन्द्र बोस

"Springing Tiger: A Study of a Revolutionary" is a biography of whom? Notes: It was the work of Hugh Toy, this book describes the Second World War and Anglo-Indian relations. Wrote about ideals, nationalism and political tact.

स्प्रिंगिंग टाइगर : ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी" किसकी जीवनी है? Notes: यह ह्यू टॉय की कृति थी, इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल-भारत संबंधों का विवरण किया गया है। इस पुस्तक में सुभाष चन्द्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श, राष्ट्रवाद और राजनीतिक चातुर्य के बारे में लिखा गया है।

11. Which country is called the 'country of Thirsty Land'?/कौन-सा देश 'प्यासी भूमि का देश' कहलाता है? - Australia/ ऑस्ट्रेलिया

Australia is called the country of thirsty land, this is because most of the area of Australia has desert areas like Great Victoria Desert, Great Sandy Desert, Great Gibson Desert, Sipson Desert, Tamari Desert etc.

ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग है जैसे - ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंड्री मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, सिपसन मरुस्थल, तमारी मरुस्थल आदि।

12. Kanchi was the Capital of which Dynasty?/कांची किस राजवंश की राजधानी थी?-Pallava Dynasty/पल्लव राजवंश

Kanchipuram was the capital of the Pallavas. The founder of the Pallava dynasty is considered to be Simhavarman I, while the last ruler of the Pallava dynasty is Aparajitvarman./पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश (Pallav Vansh) का संस्थापक सिंहवर्मन प्रथम को माना जाता है जबकि पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजितवर्मन है।

The Pallavas ruled for about 600 years in the Telugu and Tamil regions. The rulers of this dynasty considered themselves as Kshatriyas. The Pallava dynasty of South India tells the story of the glory of Indian history./तेलुगु और तमिल क्षेत्र में पल्लवों ने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया। इस वंश के शासक अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। दक्षिण भारत का पल्लव वंश भारतीय इतिहास के गौरव की गाथा बयां करता है।

13. What is the Full form of BCD in computer?/कंप्यूटर में बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है?- Binary-Coded Decimal/बाइनरी-कोडेड दशमल

Binary Coded Decimal (BCD) is a system of writing numerals that assigns a four-digit binary code to each of the digits 9 through 0 in the decimal (base-10) numeral system./बाइनरी कोडेड दशमलव (बीसीडी) अंकों को लिखने की एक प्रणाली है जो दशमलव (बेस -10) अंक में 9 से 0 प्रत्येक अंक को चार अंकों का बाइनरी कोड प्रदान करता है

Decimal	Binary
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

14. Which famous revolutionary set up base Satar river in Jhansi in the 1920's using alias, Pandit Harishankar Brahmachari? 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उप का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? -

Chandrashekhar Azad/चंद्रशेखर आजाद

Chandrashekhar Azad, a famous revolutionary to practice shooting in the forests of Oraksha (15 km from Jhansi), lived in a hut under the name of Pandit Harishankar Bahmachari. This hut was situated on the bank of river Satar. It is noteworthy that Chandrashekhar Azad was born on 23rd July, 1906 in Bhabra village of Madhya Pradesh./ओरक्षा के वनों (झांसी से 15 किमी. दूर) में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। यह कुटिया सतार नदी के किनारे पर अवस्थित थी। ध्यातव्य है कि चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को मध्य प्रदेश के भाबरा गाँव में हुआ था।

15. Name the Buddhist text that comprises rules for monks. उस बौद्ध ग्रन्थ का नाम बताइए, जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। - Vinaya Pitaka/विनय पिटक

We get detailed knowledge about Buddhism from 'Tripitaka' (Vinayapitaka, Suttapitaka and Abhidhammapitaka)./बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान 'त्रिपिटक' (विनयपिटक, सूत्रपिटक एवं अभिधम्मपिटक) से प्राप्त होता है।

In the Sutta Pitaka, the religious thoughts and teachings of Buddha have been compiled in the form of dialogues./सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों को संवादों के रूप में संकलित किया गया है।

The Vinaya Pitaka contains a collection of disciplinary rules made for the monks and nuns of the Sangha./विनयपिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाये गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है।

The philosophical explanation of Buddhism is given in the Abhidhamma Pitaka./अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है।

According to the Buddhist tradition, this Pitaka was compiled by Moggilputta Tissa in the Third Buddhist Council held during the time of Ashoka./बौद्ध परम्परा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में सम्पन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोग्गिलपुत्त तिस्स ने किया।

16. India's first indigenously made film| in colour was /भारत की पहली स्वदेश-निर्मित रंगीन फिल्म थी। - Kisan Kanya/किसान कन्या

Kisan Kanya was India's first indigenously produced color film directed by Ardeshir Irani. It was exhibited in 1937. India's first film was 'Raja Harishchandra' and the first Bolli film was 'Alam Ara'./भारत की पहली स्वदेश-निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी जिसके निर्देशक आर्देशिर ईरानी थे। यह 1937 में प्रदर्शित की गयी। भारत की प्रथम मक फिल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' तथा प्रथम बोलली फिल्म 'आलम आरा' थी।

17. The Bokaro Steel Plant was set up in India in 1964 with collaboration./भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में.....के सहयोग से की गई थी। - Soviet/सोवियत

Indian Steel Plant - State - Partner Countries	भारतीय इस्पात - संयंत्र - राज्य-सहयोगी देश
1.Bokaron Steel Plant-Jharkhand-Soviet Union	बोकारों इस्पात संयंत्र -झारखण्ड-सोवियत संघ
2.Bhilai Steel Plant - Chhattisgarh - Soviet Union	भिलाई इस्पात संयंत्र -छत्तीसगढ़ -सोवियत संघ
3.Rourkela Steel Plant-Odisha-Germany	राउरकेला स्टील प्लांट-ओडिशा -जर्मनी
4.Durgapur Steel Plant - West Bengal - UK	दुर्गापुर स्टील प्लांट -पश्चिम बंगाल -ब्रिटेन

18. The popular sword dance in the Kumaun region of Uttarakhand is called उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है। - Chholiya/छोलिया

Cholia is a popular dance performed with sword in the Kumaon region of Uttarakhand. This dance is performed on the occasion of marriage and other auspicious occasions./छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य विवाह के अवसर तथा अन्य शुभ अवसर पर किया जाता है।

19. is the largest earthen dam in India and second largest in Asia. The dam is named after the son of Mahabali, who was the king of Kerala./ भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। - Banasura Sagar Dam/बाणासुर सागर बांध

Name of the dam – River concerned – State	बाँध का नाम-सम्बन्धित नदी -राज्य
1.Banasura Sagar Dam-Karamanthodu River-Kerala	बाणासुर सागर बाँध-करमनथोडु नदी -केरल
2.Nagarjuna Sagar Dam - Krishna River - Telangana	नागार्जुन सागर बाँध-कृष्णा नदी-तेलंगाणा
3.Krishnaraja Sagar Dam, Kaveri, Hemavati and Lakshmana Tirtha River – Karnataka	कृष्णराज सागर बाँध कावेरी, हेमावती एवं लक्ष्मण तीर्थ नदी -कर्नाटक
4.Metur Dam - Kaveri - Tamil Nadu	मेटूर बाँध-कावेरी-तमिलनाडु

20. Who was the political guru of Gopal Krishna Gokhale?/गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु कौन थे?- M.G. Ranade/एम.जी. रानाडे

Gopal Krishna Gokhale, who was a pioneer in the Indian freedom struggle, was a great freedom fighter as well as a well -known politician. He inspired Gandhiji to fight for the country. He was the political guru of the Father of the Nation Mahatma Gandhi/भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहे गोपाल कृष्ण गोखले महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी थे. उन्होंने गांधी जी को देश के लिए लड़ने की प्रेरणा दी. वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे

Gopal Krishna Gokhale was a well-known face of the Indian National Crowds. He raised his voice against the policies of the British government. On the strength of his talent, he later became famous as a public leader./गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जाने-माने चेहरे थे. उन्होंने लगाता ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. अपनी प्रतिभा के दम पर वे आगे चलकर जननेता के रूप में प्रसिद्ध हुए.

He also launched a movement against casteism and untouchability. In 1912, at the invitation of Gandhiji, he himself went to South Africa and opposed the continued apartheid there./उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी आंदोलन चलाया था. 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर वह खुद भी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां जारी रंगभेद का विरोध किया.

21. Which architect has designed the India Gate in New Delhi? नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? - **Edwin Lutyens/एडविन लुटियंस**

Famous historical places of India and its main architect	भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान एवं उसके वास्तुकार प्रमुख स्थान
Calcutta-Job Charnock	कलकत्ता-जॉब चारनॉक
India Gate - Sir Edwin Lutyens	इंडिया गेट-सर एडविन लुटिएंस
Parliament House - Herbert Baker	संसद भवन-हर्बर्ट बेकर
Chandigarh-Lt. carbusier	चंडीगढ़-ली. कार्बुसियर
Rashtrapati Bhavan - Sir Edwin Lutyens	राष्ट्रपति भवन-सर एडविन लुटिएंस

22. How many nuclear power plants are in operation in India as of October 2022?
अक्टूबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत के कितने नाभिकीय शक्ति संयंत्र संचालन में हैं? -
Seven/सात

वर्तमान में भारत में 7 नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की कुल 22 इकाइयाँ संचालन में हैं।

पावर स्टेशन-राज्य

1. रावतभाटा -राजस्थान
2. कुडनकुलम-तमिलनाडु
3. केगा-कर्नाटक
4. काकरापारा-गुजरात
5. कलपक्कम-तमिलनाडु
6. नरौरा -उत्तर प्रदेश

23. Who wrote the famous Bangla novel 'Pather Panchali'? प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास 'पथेर पांचाली' के लेखक कौन हैं? - Bibhutibhushan Bandopadhyay/विभूतिभूषण बंदोपाध्याय

Vibhutibhushan Bandyopadhyay was a famous Bengali writer and novelist. He is particularly known for his epic Pather Panchali, on which noted filmmaker Satyajit Khya also produced the film Kalalokapaniya./ विभूतिभूषण बंदोपाध्याय बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार थे। वे अपने महाकाव्य पाथेर पांचाली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं जिसके ऊपर प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजित ख्य कलालोकपनिया फिल्म का निर्माण भी किया था।

24. Which among the following articles of Constitution of India gives the power to the Governor of a state to promulgate the ordinances?/भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति देता है? - 213

The Governor of an Indian state draws ordinance making power from Article 213 of Indian Constitution. This article empowers governor to promulgate ordinance on an urgent matter and such ordinance shall have same force and effect as an Act of Legislature of the State.

भारतीय राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 से अध्यादेश बनाने की शक्ति प्राप्तकरता है। यह अनुच्छेदराज्यपाल को एक जरूरी विषयपर अध्यादेश लाने का अधिकार देता है और इस अध्यादेश में राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा।

25. In which part of India is the festival 'Moatsu' celebrated?/मोहत्सू (Moatsu) पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है ? - Nagaland/नागालैंड

Moatsu festival in the state of Nagaland, India. is celebrated. Other festivals of Nagaland are Hornbill Festival, Sekernei Festival, Bamboo Day Festival, Angmong Festival, Tokhu Imong Festival, Yamshe Festival etc. Mohts is celebrated annually by the Lohar Ao tribe during the first week of May. Mohatsu Festival is an annual festival celebrated after the sowing season./मोहत्सू (Moatsu) पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड के अन्य

त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल, सेकेरनेई फेस्टिवल, बाँस दिवस समारोह, आंगमोंग फेस्टिवल, तोखू इमोंग फेस्टिवल, यमशे फेस्टिवल आदि हैं। मोहत्स, लोहार एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मोहत्सु फेस्टिवल एक वार्षिक त्योहार है, जिसे बुवाई के मौसम के बाद मनाया जाता है।

26. India's first beam weapon KALI-5000 was developed by...../ भारत के पहले बीम वेपन KALI-5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? - DRDO & BARC/डीआरडीओ और बार्क

Kali 5000 is the technology through which the enemy's weapons can be destroyed in the air itself by attacking with an invisible beam like laser. Kali is said to be capable of shooting down enemy missiles, fighter aircraft, even satellites in space./काली 5000 वह तकनीक है, जिसके जरिए लेजर जैसी अदृश्य बीम से हमला करके दुश्मनों के हथियारों को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। दुश्मन की मिसाइलें, लड़ाकू विमान, यहां तक कि काली को अंतरिक्ष में उपग्रहों को भी मार गिराने में सक्षम बताया जाता है।

27. The mission on Nano Science and Technology (Nano Mission) was launched in नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी (नैनो मिशन) मिशन की शुरुआत में की गयी थी। - 2007

The Nano Science and Technology Mission was started by the Government of India in 2007. It is being implemented by the Department of Science and Technology under the Ministry of Science and Technology. As a result of the efforts led by the Nano Mission, India is currently ranked among the top five countries in the world in terms of scientific publications in the field of nanoscience and technology./नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में की गयी थी। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकीय मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों के मामले में विश्व के शीर्ष पांच देशों में शामिल है।

28. How many columns are there in a sheet of Excel 2010? एक्सेल 2010 की एक शीट में कितने कॉलम होते हैं? - 16384

एक्सेल 2010 की एक शीट में 16384 कॉलम होते हैं।

Version - Row - column

2003 - 65536 - 256
2007 - 1048576 - 16384
2010- 1048576 - 16384

29. The largest unit of memory of a computer system? कम्प्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? - Yottabyte/योटाबाइट

8 बिट्स = 1 KB
1024 KB = 1 MB
1024 MB = 1 GB
1024 GB = 1 TB
1024 TB = 1 PB
1024 PB = 1 EB
30 = 1 YB

30. Who coined the slogan "Simon go back"?/“साइमन गो बैक” नारे का निर्माण किसने किया था?-Yusuf Meher Ali/यूसुफ मेहर अली

Joseph showed his organization capacity by organizing the fee increase in the college and protest against police firing on students in Bangalore and striking mill workers./कालेज में फीस वृद्धि और बेंगलूर में छात्रों पर पुलिस की गोलीबारी के विरोध तथा हड़ताली मिल मजदूरों के समर्थन में जनसभाएं आयोजित कर यूसुफ ने अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया।

Nervous with his abilities, the British rule stopped him from practicing in the Bombay High Court. When the matter of giving some rights to India came to light, a commission was formed in the chairmanship of Simon for it./उनकी क्षमताओं से घबराई ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने तक से रोक दिया। जब भारत को कुछ अधिकार दिए जाने की बात सामने आई तो उसके लिए साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया।

Joseph was the only Indian member of this commission. In December 1927, the Indian National Congress passed a proposal for boycott of Simon Commission. On the night of February 3, 1928, members of the Simon Commission landed at the Bombay's Mole port. Then socialist young Yusuf Meher Ali gave the slogan of Simon Go Back. After this, the British government lashed out at the protesters./यूसुफ इस आयोग के एकमात्र भारतीय

सदस्य थे। दिसंबर 1927 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। 3 फरवरी, 1928 की रात में बंबई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने नारा लगाया साइमन गो बैक का नारा दिया। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी बरसाई।

31. In which place did Shah Mal lead the revolt in 1857?/1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? - Baraut/बड़ौत

Shah Mal also known as Shahmal Singh. He did the element of Jato of Baraut (U.P.) during the revolt of 1857./शाह मल जिसे शाहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत (उ.प्र.) के जाटों का तत्व किया था।

On May 10, 1857, the rebels, after announcing an armed rebellion in Meerut, proceeded towards Delhi, and on May 11, 1857, at dawn, Delhi was captured by the rebels. After reaching Delhi, the rebels declared the then Mughal emperor Bahadur Shah Zafar as the leader of the rebellion and the emperor of India./10 मई, 1857 को विद्रोही मेरठ में सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई, 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली पहुँचने के बाद विद्रोहियों ने तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता तथा भारत का सम्राट घोषित कर दिया था।

Bahadur Shah Zafar's representative in Delhi, Bakht Khan, provided leadership to this rebellion./दिल्ली में बहादुर शाह जफर के प्रतिनिधि बख्त खां ने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था।

Nana Saheb gave leadership to this rebellion in Kanpur. During this Tantya Tope helped Nana Saheb./कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब ने नेतृत्व प्रदान किया। इस दौरान तांत्या टोपे ने नाना साहब की मदद की थी।

Begum Hazrat Mahal took the lead in Lucknow and declared her minor son Birjis Qadir the Nawab of Lucknow./लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया।

Rani Lakshmibai led in Jhansi. In this war, the English army was given leadership by General Hurose./झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को जनरल ह्यूरोज ने नेतृत्व प्रदान किया था।

Kunwar Singh led in Jagdishpur, Khan Bahadur Khan in Ruhelkhand, Maulvi Ahmadullah in Faizabad and Tantya Tope in Gwalior./जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने रुहेलखंड में खान बहादुर खान, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह और ग्वालियर में तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया।

32. The South Indian counterpart of the North Indian instrument 'Nagada' is: उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र 'नगाड़ा' के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र कौन सा है? - Chenda/छेदा

The North Indian musical instrument is the nagara while its equivalent South Indian instrument is the Chenda./उत्तर भारतीय वाद्ययंत्र नगाड़ा है जबकि इसी के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्ययंत्र छेदा (Chenda) है।

- Sitar – Pt. Ravi Shankar, Umashankar Mishra, Buddhaditya Mukherjee, Vilayat Khan, Shahid Parvez, Vandehsan.
- सितार – पं. रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदेहसन ।
- Sarod – Amjad Ali Khan, Alauddin Khan, Ali Akbar Khan, Vishwajitray Chaudhary, Mukesh Sharma, Buddhadevdas Gupta.
- सरोद – अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीतराय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेवदास गुप्ता ।
- Santoor – Shivkumar Sharma, Bhajan Sopari.
- संतूर – शिवकुमार शर्मा, भजन सोपारी ।
- Shehnai – Bismillah Khan, Ali Ahmed, Hussain Khan, Dayashankar Jagannath.
- शहनाई – बिस्मिल्ला खां, अली अहमद, हुसेन खां, दयाशंकर जगन्नाथ ।
- Flute – Hariprasad Chaurasia, Patralal Ghosh, Rajendra Kulkunin, V. Kunjamani.
- बाँसुरी – हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोष, राजेन्द्र कुलकुणी, वी. कुंजमणि ।
- Tabla – Zakir Hussain, Alla Rakha Khan, Gudai Maharaj, Kishan Maharaj, Latif Khan, Sukhwinder Singh.
- तबला – जाकिर हुसैन, अल्ला रखा खां, गुदै महाराज, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह ।
- Violin – TN. Krishnan, Dr. N. Rajam, L. Subrahmanyam.
- वायलिन- टीएन. कृष्णन, डॉ. एन. राजम, एल. सुब्राह्मण्यम् ।

- Pakhawaj – Gopal Das, Thakur Laxman Singh, Chhatrapati Singh, Rehman Khan.
- पखावज- गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खां ।

33. Which community of Rajasthan has been following block printing since the last three centuries?/राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली तीन शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? - Chhippa/छिप्पा

Block printing is one of the traditional techniques, which is attributed to the 'Chhippa' community of Rajasthan. The people of the Chhippa community are the people of the ancient weaving society of India. The word 'Chhipa' is derived from two words of Nepali language 'Chhi' meaning to dye and 'Pa' meaning to dry in the sun. People of this community have been doing block printing in Rajasthan for the last three centuries./ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के 'छिप्पा' समुदाय को जाता है। छिप्पा समाज के लोग भारत के पुरातन बुनकर समाज के लोग हैं। 'छिपा' शब्द नेपाली भाषा के दो शब्दों 'छी' अर्थात् डाई करना एवं 'पा' अर्थात् धूप में सुखाना से मिलकर बना है। इस समुदाय के लोग राजस्थान में पिछले तीन शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग करते आ रहे हैं।

34. Who called Subhash Chandra Bose the Deshnayak?/शुभाष चन्द्र बोस को देशनायक किसने कहा?- Rabindranath Tagore/रबींद्रनाथ टैगोर

Subhash Chandra Bose (also known as Netaji) is known for his role in India's freedom movement. A partner of the non-cooperation movement and a leader of the Indian National Congress, he was part of the more militant wing and was known for advocating socialist policies./सुभाष चंद्र बोस (जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है) भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। असहयोग आंदोलन के एक भागीदार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता, वह अधिक उग्रवादी विंग का हिस्सा थे और समाजवादी नीतियों की वकालत के लिए जाने जाते थे।

German dictator Adolf Hitler called Subhash Chandra Bose as 'Netaji' for the first time. Along with Netaji, Sushabh Chandra Bose is also called Desh Nayak. It is said that Subhash Chandra Bose, the title of Desh Nayak,

received Rabindranath Tagore/जर्मन के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहली बार 'नेताजी' कहकर बुलाया था. नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है. कहा जात है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रवीन्द्रनाथ टैगोर से मिली थी

35. Where is the memorial of Bhagat Singh located/भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है - Ferozepur (Punjab)/फिरोजपुर (पंजाब)

Shaheed Bhagat Singh is the tomb of Balidani Bhagat Singh Rajguru and Sukhdev at Hussainiwala in Ferozepur. The village was in Pakistan before 1960./शहीद भगत सिंह फिरोजपुर स्थित हुसैनीवाला में बलिदानी भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव का समाधि स्थल है। यह गांव 1960 से पहले पाकिस्तान में था।

It is located on the banks of the Sutlej River and on the border with India of India./यह सतलुज नदी के किनारे और भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा पर स्थित है।

36. The position of Vice President is taken from which country in the Indian constitution?/ उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है ? - America / अमेरिका

- The governor of each state plays an important role in the operation of the democratically elected government there./प्रत्येक राज्य का राज्यपाल वहाँ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- The role of the Governor has been described in Articles 153 to 162 of the Indian Constitution.\ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है।
- Article 153 - Every state in the country shall have a Governor. Also a person can be appointed as the governor of two or more states.
- अनुच्छेद 153 -देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
- According to Article 155, the Governor is appointed by the President./अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

➤ Article 157 and Article 158 of the Constitution lay down the essential eligibility for the post of Governor, which are as follows: /संविधान के अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद हेतु आवश्यक पात्रता निर्धारित की गई है जो निम्नलिखित हैं:

1. He should be an Indian citizen./वह भारतीय नागरिक हो।
2. He must be at least 35 years of age./उसकी उम्र कम-से-कम 35 वर्ष हो।
3. He should neither be a member of either House of the Parliament nor of the State Legislature./वह न तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और न ही राज्य विधायिका का।

Article 163 of the Constitution gives discretionary power to the Governor, that is, he is not bound to follow the advice of the Council of Ministers in his discretionary work./संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्रदान करता है अर्थात् वह स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है।

37. Hemavati is a tributary of which river?/हेमवती किस नदी की सहायक नदी है? -

Cauvery/कावेरी

Kaveri River/कावेरी नदी

- Origin: Brahmagiri Range Karnataka
- उद्गम स्थल— ब्रह्मगिरि श्रृंखला कर्नाटक
- मुहाना — बंगाल की खाड़ी
- Length 800 km
- लम्बाई — 800 किमी०
- its major tributaries/इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ
- In the north are Hemavati, Lokapavani, Shimsa and Arkavati,
- उत्तर में हेमावती , लोकापावनी , शिमसा व अर्कवती ,
- South Lakshmanatirtha, Kabini, Suvarnavati, Bhavani and Amravati.
- दक्षिण - लक्ष्मणतीर्थ , कबीनी , सुवर्णवती , भवानी और अमरावती

38. How many years are the members of the Public Accounts Committee?/लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? - 1 year/1 वर्ष

क्र.सं.	समिति का नाम	सदस्यों की संख्या	कार्यकाल	सदस्य नामनिर्देशित अथवा निर्वाचित
1.	प्राक्कलन समिति	30	1 वर्ष	लोक सभा द्वारा निर्वाचित
2.	लोक लेखा समिति	22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)	1 वर्ष	दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित
3.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	22 (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा)	1 वर्ष	दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित

39. Who was the first President of the Indian National Congress, founded in 1885?- 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष (प्रेजिडेंट) कौन थे?- W.C. Banerjee/डब्ल्यू. सी. बैनर्जी

बैनर्जी

The first President of the Indian National Congress, established in 1885 AD, was W. C. Banerjee. In the first session which was held in Bombay, 72 delegates participated and the objective resolution of the Congress was decided. The president of the second Congress was Dadabhai Naoroji, the third was Badruddin Tyabji and the fourth (Allahabad) was headed by George Yule. /1885 ई. में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन जिसका आयोजन बंबई में हुआ, में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा कांग्रेस का उद्देश्य प्रस्ताव तय किया गया। द्वितीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी, तृतीय के बदरुद्दीन तैयबजी तथा चौथे (इलाहाबाद) के अध्यक्ष जार्ज यूले थे।

40. Gangubai Hangal was an Indian vocalist of the Hindustani classical tradition who was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 1973. From which of the following musical Gharanas did she belong?/गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थीं, जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थीं?- Kirana Gharana/किराना घराना

Gangubai's autobiography titled 'Nanna Badukina Hadu (Music of My Life)' was published. He was awarded the Padma Bhushan in 1971, the Sahitya Natak Akademi Award in 1973 and the Padma Vibhushan in 2002./गंगूबाई की आत्मकथा 'नन्ना बदूकिना हादु (मेरे जीवन का संगीत)' शीर्षक से प्रकाशित हुई। उन्हें 1971 में उन्हें पद्म भूषण, 1973 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

41. In which year was International Booker Prize established?/अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी?- 2005

The International Booker Prize was started in 2005 as the Man Booker International Prize. It was initially a biennial prize, and stipulated that the winning author be a citizen of the United Kingdom. But in 2015, this condition was removed and it became free for authors from all over the world. Ismail Qadri was the first winner of this award. In 2019 the "Man Group" stopped sponsoring it and since then it is simply known as the International Booker Prize. This award is different from the Booker Prize. अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में हुई थी | यह शुरू में एक द्विवार्षिक पुरस्कार था, और इसमें शर्त थी कि विजेता लेखक यूनाइटेड किंगडम का नागरिक होना चाहिए | किंतु 2015 में यह शर्त हटा ली गई और यह दुनिया भर के लेखकों के लिए मुक्त हो गया | इस्माइल कादरी इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे | 2019 में “मैन ग्रुप” ने इसका प्रायोजन बंद कर दिया और तब से यह केवल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है | यह पुरस्कार बुकर पुरस्कार से भिन्न है |

Indian author Gitanjali Shree's Hindi novel "Ret Samadhi (Tomb of Sand)" translated into English by Daisy Rockwell has been declared the winner for the International Booker Prize 2022.

भारतीय लेखिका गीतांजली श्री के हिन्दी उपन्यास “रेत समाधि (Tomb of Sand)” जिसे डेज़ी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनूदित किया, को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के लिए विजेता घोषित किया गया।

42. Ustad Hassu Khan, Ustad Haddu Khan and Ustad Nathu Khan were exponents of the _____ Gharana./उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान _____ घराने के प्रतिपादक थे। - Gwalior/गवालियर

Agra Gharana - Agra Gharana is one of the famous gharanas of Hindustani music. Tansen's son-in-law Haji Sujan Saheb was the founder of the Agra Gharana.

आगरा घराना- आगरा घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। आगरा घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब थे।

Founders: Haji Sujan Khan and Ustad Ghaghe Khuda Baksh

संस्थापक: हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्घे खुदा बख्श

Artist: Fayaz Khan, Latafat Hussain Khan, Dinkar Kakini

प्रतिपादक:, फैयाज़ खान, लताफ़त हुसैन खान, दिनकर काकिनी

Gwalior Gharanastarted with the reign of the great Mughal emperor Akbar (1542–1605). During the time of Mughal kings Ustad Nathan Pir Bakhsh and his maternal grandsons werethe legendary Haddu, Hassu and Nathu Khan. The

main musician in the court at the time was Ustad Bade Mohammad Khan who was famous for his taan baazi. /ग़्वालियर घराने की शुरुआत महान मुगल बादशाह अकबर (1542-1605) के शासनकाल से हुई। मुगल राजाओं के समय में उस्ताद नाथन पीर बख्श और उनके नाती प्रसिद्ध हद्दू, हस्सू और नाथू खान थे। उस समय दरबार में मुख्य संगीतकार उस्ताद बड़े मोहम्मद खान थे जो अपनी तान बाजी के लिए प्रसिद्ध थे।

किराना घराना

Founders: Abdul Karim Khan and Abdul Wahid Khan

संस्थापक: अब्दुल करीम खाँ और अब्दुल वाहिद खान

Exponents: Sawai Gandharva, Sureshbabu Mane, Prabha Atre, disciple of Hirabai Badodkar, Manik Verma, Sureshbabu Mane

प्रतिपादक: सवाई गंधर्व, सुरेशबाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बादोडकर की शिष्या, माणिक वर्मा, सुरेशबाबू माने

Patiala Gharana/पटियाला घराना

Founders: Ustad Fateh Ali Khan, Ustad Ali Baksh

संस्थापक: उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अली बख्श

Artist: Bade Ghulam Ali Khan, Ajoy Chakraborty, Raza Ali Khan, Begum Akhtar, Nirmala Deni, Naina Devi, Parveen Sultana

प्रतिपादक: बड़े गुलाम अली खाँ, अजॉय चक्रवर्ती, रज़ा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देनी, नैना देवी, परवीन सुल्ताना

43. During which festival the Nongkrem dance is performed by the Khasi tribes?

/खासी जनजातियों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किस त्योहार के दौरान किया जाता है? - Wangla /

वांगला

Nongkrem Dance Festival (held annually in November)

is a five day festival which is celebrated for the harvest thanksgiving by the Khasi tribe.

The Nongkrem Dance is the most important festival of the Khyrim state./नोंगक्रेम डांस

फेस्टिवल (प्रतिवर्ष नवंबर में आयोजित) पांच दिवसीय त्योहार है जो खासी जनजाति द्वारा

फसल धन्यवाद के लिए मनाया जाता है। नोंगक्रेम नृत्य खैरिम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण

त्योहार है।

Ponung dance is a popular and the most common folk art form practiced in the Arunachal

Pradesh state of India./पोंग नृत्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित एक लोकप्रिय

और सबसे आम लोक कला है।

Kud dance is a famous dance form of Jammu and Kashmir. It is a ritual dance performed in honor of the Kud folk deity./कुद नृत्य जम्मू-कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यह कुद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है।

44. Who called Rabindranath Tagore the "Great Sentinel"?/रवीन्द्रनाथ टैगोर को किसने "महान प्रहरी" कहा था?- Mahatma Gandhi/महात्मा गाँधी

Gurudev Rabindranath Tagore was called by Mahatma Gandhi by 'Mahan Prahari'./गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर को 'महान प्रहरी' महात्मा गाँधी ने कहा था।

Vishwa Bharati University is a public research Central University and an institution of national importance located in Santiniketan, West Bengal, India. It was founded by Rabindranath Tagore, who called it Vishwa-Bharati, which means the world dialogue with India./विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो भारत के पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में स्थित है। इसकी स्थापना रवीन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व-भारती कहा था, जिसका अर्थ भारत के साथ दुनिया का संवाद है।

Poet Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection Gitanjali published in London in 1913. The importance of this award increased even more due to being given to an Indian for the first time. This honor established Tagore's literary reputation worldwide./कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में लंदन में प्रकाशित अपने संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। पहली बार किसी भारतीय को दिए जाने से इस पुरस्कार का महत्व और भी बढ़ गया। इस सम्मान ने दुनिया भर में टैगोर की साहित्यिक प्रतिष्ठा स्थापित की।

45. In which year the Bharat Nirman program was started? - The Government of India launched a program named 'Bharat Nirman' on ./भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया ?- 16 December 2005

The Government of India started a program named 'Bharat Nirman' on 16 December 2005./भारत सरकार ने 16 दिसम्बर, 2005 को 'भारत निर्माण' नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की।

To provide a better life to the rural people, the Government of India launched a program called 'Bharat Nirman' on 16 December 2005. The scheme mainly focused on 6 sectors which included electricity, water, roads, irrigation, telecommunication and housing in rural areas of the country./ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसम्बर, 2005 को 'भारत निर्माण' नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी जिसमें बिजली, पानी सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल था।

The scheme mainly focused on 6 sectors, which included electricity, water, roads, irrigation, telecommunication and housing in rural areas of the country./यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जिसमें बिजली, पानी सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास शामिल था।

46. Which state still does not have Panchayati Raj system?/किस राज्य में अब तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है?- Nagaland/नागालैंड

Panchayati Raj system is absent in Delhi, Nagaland, Meghalaya and Mizoram./पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है।

Panchayati Raj system is absent in Delhi, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. Panchayati Raj establishes the village local government which plays an important role especially in the development of primary education, health, agricultural development, women and child development. Balwant Rai Mehta is also known as the father of Panchayati Raj. According to Article 243M of the Indian Constitution, the Panchayati Raj system exists in all states and union territories, except Nagaland, Meghalaya and all union territories except Mizoram and Meghalaya./पंचायती राज व्यवस्था दिल्ली, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं है। पंचायती

राज ग्राम स्थानीय सरकार की स्थापना करता है जो विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, महिला और बाल विकास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एम के अनुसार, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और मेघालय को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है।

47. Whose royal court poet was the famous poet Vilhad?/ प्रसिद्ध कवि विल्हड किसका राज दरबारी कवि था? - [Vikramaditya/विक्रमादित्य](#)

Bilhan was a famous poet of Kashmir. His famous work is Chaurapanchasika. His second famous work is Vikramankadevcharit which is a history book. Bilhan's Vikramankadevcharita chronicles the feats of the Chalukya king Vikramaditya Pancham of Kalyan./बिल्हण कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे | इनकी प्रसिद्ध रचना चौरपंचाशिका है। इनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना विक्रमांकदेवचरित है जो इतिहास ग्रन्थ है। बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है।

48. In which year the Consumer Protection Act was passed?/उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? - [1986](#)

The abbreviation of this act, regulated by the Indian Parliament, is the Consumer Protection Act 1986, whose jurisdiction is all over India. The new Consumer Protection Act, 2019 came into force on July 20, 2020./भारतीय संसद द्वारा विनियमित इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, जिसकी अधिकारिकता समस्त भारतवर्ष है। 20 जुलाई, 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू किया गया।

49. Who among the following is the author of Ramcharitram?/ निम्नलिखित में से कौन रामचरित्रम के लेखक हैं? - [Sandhyakar Nandi/संध्याकर नंदी](#)

Ramcharitram was written by Sandhyakar Nandi. Sandhyakar Nandi was a court poet in the Pala dynasty. Sandhyakar Nandi was patronized by Madanpal./रामचरित्रम को संध्याकर नंदी ने लिखा था। पाल वंश में संध्याकर नंदी एक दरबारी कवि थे। संध्याकर नंदी को मदनपाल ने संरक्षण दिया था।

50. In which Governor-General's reign railway lines in India was established? /भारत में किस गवर्नर-जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना की गई थी ?- Lord Dalhousie/लॉर्ड डलहौजी

A scheme for the railway system in India first appeared in 1832, but no steps were taken for this for more than a decade. In 1844, India's Governor General Lord Harding allowed private entrepreneurs to set up a rail system in India. Two new railway companies were formed and the East India Company was asked to help them./भारत में रेल प्रणाली के लिए एक योजना पहली बार 1832 में सामने आई थी, लेकिन एक दशक से अधिक समय तक इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। 1844 में, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी उद्यमियों को भारत में एक रेल प्रणाली स्थापित करने की अनुमति दी। दो नई रेलवे कंपनियां बनाई गईं और ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी सहायता करने के लिए कहा गया।

The first train in India started in 1851. A year and a half later, the first passenger train service was inaugurated in 1853 between Boribandar Bombay and Thane. Counting a distance of 34 km (21 mi), it was drawn by three engines, Sahib, Sindh and Sultan. It was a formal birth of railway in India./भारत में पहली ट्रेन 1851 में चालू हुई। डेढ़ साल बाद, 1853 में पहली यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन बोरीबंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच किया गया। 34 किमी (21 मील) की दूरी तय करते हुए, इसे तीन इंजनों, साहिब, सिंध और सुल्तान द्वारा खींचा गया। यह भारत में रेलवे का औपचारिक जन्म था।

The formal opening ceremony was held on 16 April 1853, when 14 railway trains carrying around 400 guests left the sack bunder "amidst the loud applause of a huge crowd and 21 cannon salute."/औपचारिक उद्घाटन समारोह 16 अप्रैल 1853 को किया गया था, जब लगभग 400 मेहमानों को ले जाने वाली 14 रेलवे गाड़ियों ने बोरी बंडर को "एक विशाल भीड़ के जोरदार तालियों और 21 तोपों की सलामी के बीच छोड़ दिया था।"

On 15 August 1854, the first passenger train that covered a distance of 24 miles from Hooghly from Howrah station, thus the first section of the East Indian Railways was opened

for public traffic, which started railway transport in the eastern part. Subcontinent. In the south, the Madras Railway Company opened the first line on 1 July 1856. It lasted 63 miles at a distance of 63 miles between Veyarspandy and Valjah Road./15 अगस्त 1854 को हुगली से 24 मील की दूरी तय करने वाली हावड़ा स्टेशन से निकलने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी इस प्रकार ईस्ट इंडियन रेलवे के पहले खंड को सार्वजनिक यातायात के लिए खोल दिया गया, जिसके पूर्वी हिस्से में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। उपमहाद्वीप। दक्षिण में मद्रास रेलवे कंपनी ने 1 जुलाई 1856 को पहली लाइन खोली। यह 63 मील की दूरी पर वेयारस्पेंडी और वालजाह रोड के बीच चली।

51. Dogri is the language spoken in:/डोंगरी भाषा निम्न राज्य में बोली जाती है। -Jammu & Kashmir/जम्मू तथा कश्मीर

Dogri is a language spoken in the Indian state of Jammu, Kangra in Himachal and some provinces of northern Punjab./डोंगरी भारत के जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रान्त में बोली जाने वाली एक भाषा है।

In the year 2003, it has been included in the Eighth Schedule of the Indian Constitution./वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

52. In a work sheet in MS Excel, what is the shortcut key to hide entire row?/एम.एस. एक्सेल (MS Excel) की वर्कशीट में सम्पूर्ण कतार को छुपाने के लिये शॉर्ट की क्या है? - Ctrl+9

- Ctrl + 2 changes a line, paragraph, or all highlighted text to have double spacing.
- Ctrl+9 is a keyboard shortcut most often used to switch to the ninth tab in an Internet browser or other programs with tab support.
- Ctrl+N -Create a new document.
- Ctrl+R is a keyboard shortcut most often used to refresh the page in an Internet browser.

53. "IC chips' for computers are usually made of: /कम्प्यूटर का 'आई.सी. चिप' (Ic chips) सामान्यतः किसका बना होता है - Silicon /सिलिकॉन

- The integrated circuit chip in a computer is made of silicon. The full form of IC Chips is Integrated Circuit Chips./कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन से बनी होती है। आईसी चिप्स का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स है।

- It is made of semiconductor material which is usually silicon./यह अर्धचालक सामग्री से बना होता है जो आमतौर पर सिलिकॉन होता है।
- An integrated circuit (IC) is an electronic device consisting of several functional elements such as transistors, resistors, condensers, etc./एक एकीकृत सर्किट (आईसी) एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, कंडेनसर इत्यादि जैसे कई कार्यात्मक तत्व शामिल हैं।

54. What is the control unit's function in the CPU: /सी.पी.यू. (CPU) में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। To decode program instructions/प्रोग्राम निर्देशों को डीकोड करना

The control unit of the central processing unit regulates and integrates the operations of the computer./सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की नियंत्रण इकाई कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित और एकीकृत करती है।

55. To which ocean the Panama Canal joins the Atlantic Ocean?/ किस महासागर में पनामा नहर अटलान्टिक महासागर से मिलती है? - Pacific Ocean/प्रशान्त महासागर

Panama Canal/पनामा नहर-

It is located in Panama, Central America./यह मध्य अमेरिका के पनामा में स्थित है।

This canal connects the Pacific Ocean and (via the Caribbean Sea) the Atlantic Ocean./यह नहर प्रशांत महासागर और (कैरेबियन सागर होकर) अटलान्टिक महासागर को जोड़ती है।

This 82 km long canal is one of the major waterways for international trade./82 किलोमीटर लंबी यह नहर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है

Pacific Ocean/प्रशान्त महासागर: This is the Pacific Ocean, the largest and deepest ocean in the world. The world's second largest ocean is more than twice that of the Atlantic Ocean./यह प्रशांत महासागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलान्टिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है।

56. Where is the headquarter of BRICS Bank located?/ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? -China/चीन

The headquarter of BRICS Bank is in Shanghai, the name of this bank is New Development Bank./ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई में है इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है

The full form of BRICS is Brazil, Russia, India, China and South Africa./ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।

57. With whom did Shah Jahan fight the battle of Kartarpur?/शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किससे लड़ा था? - [Guru Hargovind/गुरु हरगोविंद सिंह](#)

The Battle of Kartarpur took place on 25 April 1635. It began when the Mughal Empire attacked the city of Kartarpur, and was the last major battle of the Mughal-Sikh Wars of Guru Hargobind's period.

करतारपुर की लड़ाई 25 अप्रैल 1635 को हुई थी। यह तब शुरू हुआ जब मुगल साम्राज्य ने करतारपुर शहर पर हमला किया, और गुरु हरगोबिंद की अवधि के मुगल-सिख युद्धों की आखिरी बड़ी लड़ाई थी।

58. India won the first year 2022 Thomas Cup by defeating which country?/भारत ने किस देश को हराकर पहला वर्ष 2022 का थॉमस कप जीता? - [Indonesia/इंडोनेशिया](#)

With this victory of India, social media started trending Indian badminton team. India wins Thomas Cup 2022: India created history by defeating 14-time champion Indonesia in the final of the Thomas Cup 2022 badminton tournament on Sunday. India managed to win this badminton tournament for the first time in 73 years./भारत की इस जीत के साथ ही सोशल मीडिया भारतीय बैडमिंटन टीम ट्रेंड करने लगी. India wins Thomas Cup 2022: भारत ने रविवार को थॉमस कप (Thomas Cup 2022) बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर इतिहास रच दिया है. भारत ने 73 साल में पहली बार बैडमिंटन के इस टूर्नामेंट को जीतने में कामयाबी हासिल की.

59. Which country won the 2022 Uber Cup?/किस देश ने 2022 का उबर कप जीता? - [South Korea/दक्षिण कोरिया](#)

South Korea defeated defending champions China to win the prestigious Uber Cup championship held in Thailand's capital Bangkok. The South Korean women's team ended its 12-year wait for the Uber Cup title. In the Thomas Cup, the Indian men's team defeated their Indonesia to win the title./थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित प्रतिष्ठित उबर कप चैंपियनशिप

जीतने के लिए दक्षिण कोरिया ने गत चैंपियन चीन को हरा दिया। दक्षिण कोरियाई महिला टीम ने उबर कप खिताब के लिए अपने 12 साल के इंतजार को समाप्त कर दिया। थॉमस कप में, भारतीय पुरुष टीम ने अपने इंडोनेशिया को हराकर खिताब जीता।

60. Who was popularly known as Napoleon of ancient India?/ किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था?- [Samudragupta/समुद्रगुप्त](#)

Vicente Smith called the famous Gupta ruler Samudragupta (350-375 A.D.) the 'Napoleon of India' because of his victories. The main source of knowing the history of Samudragupta is 'Prayag Prashasti' which is composed by Harishena in Champu style. Prayag Prashasti sheds light on his victories.

प्रसिद्ध गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त (350-375 A.D) को विजयों के कारण विसेंट स्मिथ ने 'भारत का नेपोलियन' कहा है। समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत 'प्रयाग प्रशस्ति' है जिसकी रचना हरिषेण ने चम्पू शैली में की है। प्रयाग प्रशस्ति से उसकी विजयों पर प्रकाश पड़ता है।

61. Who among the following was responsible for the destruction of the famous Somnath temple on the Gujarat coast?/गुजरात समुद्रतट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? - [Mahmud of Ghazni/महमूद गजनवी](#)

Mahmud Ghaznavi attacked India 17 times between 1000 AD to 1027 AD. Mahmud's most famous attack took place in 1025 AD on the Somnath temple located on the coast of Gujarat. He destroyed the temple and went to Ghazni with the loot./महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ई. से 1027 ई. के बीच 17 बार आक्रमण किये। महमूद का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ई. में गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर पर हुआ। उसने मंदिर को नष्ट किया तथा लूट का सामान लेकर गजनी चला गया।

62. Under which article can the Parliament make rules related to citizenship and citizenship?/संसद किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता सम्बंधित नियम बना सकती है? - [Article 11](#)

Articles 5 to 10 define the eligibility for citizenship. Article 11 empowers the Parliament to make laws on matters of citizenship./अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता की पात्रता को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 11 नागरिकता के मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been brought to amend the Citizenship Act, 1955./नागरिकता) संशोधन (अधिनियम, 2019 को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिये लाया गया है।

63. When was the Inter-State Council constituted?/अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? - 1990

The Sarkaria Commission made an important recommendation to establish an Inter-State Council as an independent national forum for consultation in pursuance of the mandate defined in accordance with Article 263 of the Constitution of India. Pursuant to this recommendation, the Inter-State Council was constituted under Article 263 of the Constitution by the President's order dated May 28, 1990, whose first meeting was held on October 10, 1990./सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतरराज्यीय परिषद स्थापित किये जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसरण में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के दिनांक 28 मई, 1990 के आदेश के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी।

64. Which schedule deals with the administration of the tribal areas of the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram?/असम , मेघालय , त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है ? - Sixth Schedule/छठी अनुसूची

- Third Schedule: It mentions the oath to be taken by various office bearers (President, Vice President, Ministers, Judges of Supreme and High Court) at the time of taking office.
- तृतीय अनुसूची: इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने शपथ का उल्लेख है.
- Fourth Schedule: In this, the details of the representation of various states and union territories in the Rajya Sabha are given.
- चौथी अनुसूची: इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है.

- Fifth Schedule: It mentions about the administration and control of various Scheduled Areas and Scheduled Tribes.
- पांचवीं अनुसूची: इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।

65. Under which Article the Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha are appointed?/किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? -

Article/अनुच्छेद-93

Article 93 of the Constitution of India provides for the appointment of the Speaker and Deputy Speaker of the Lok Sabha, while Article 178 of the Constitution provides for the appointment of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly./भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, वहीं संविधान का अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है।

66. How long the law made by the Rajya Sabha under Article 249 remains in effect/राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत बनाया गया कानून कितने समय तक प्रभावी रहता है? - One year/एक साल

According to Article 249 of the Constitution, if the Rajya Sabha, by a majority of two-thirds of its members present and voting, proposes that it is necessary or beneficial in the interest of the nation, Parliament can make laws on any matter listed in the State List./संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव करें कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची में दिये गए किसी विषय पर कानून बना सकती है।

67. Which Article of the Constitution provides for review of any judgment or order passed by the Supreme Court?/सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाये गये किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन करना संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है ? - Article 137/अनुच्छेद 137

Article 127- Appointment of ad hoc judges

Article 127-तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति

Article 129- declares the Supreme Courts to be courts of record.

Article 129-उच्चतम न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है।

Article 143 - Power of President to consult Court.

अनुच्छेद 143- न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति |

68. The concept of 'carbon credit' originated from...../'कार्बन क्रेडिट' की अवधारणासे उत्पन्न हुई? - Kyoto protocol/ क्योटो प्रोटोकॉल

The Kyoto Protocol was formed in 1997, India signed and ratified the Kyoto Protocol in 2002./क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बना था, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और उसका अनुमोदन किया था।

The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005./क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था।

69. The chain of very high plateaus in Australia is called ____./ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऊँचे पठारों की श्रृंखला को _____ कहा जाता है। - Great Dividing Range/ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज

In the eastern part of Australia is found high land which runs parallel to the coast. This chain of very high plateaus is called Great Dividing Range.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ऊँची भूमि पाई जाती है जो तट के समानांतर चलती है। बहुत ऊँचे पठारों की इस श्रृंखला को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है।

70. Which of the following grassland in Australia is called as 'Parkland of Australia'/? ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को 'ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड' कहा जाता है? -

Downs/ डाउन्स

The Downs grassland in Australia is called as 'Parkland of Australia'

ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान को 'ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड' कहा जाता है।

71. Whose titles were 'Abhinav Bhoja', Andhra Bhoja, 'Yavanaraja Sthaypanacharya' etc. /अभिनव भोज, आन्ध्र भोज, 'यवनराज स्थायपनाचार्य' आदि किसकी उपाधियाँ थी- Krishnadev Rai/कृष्णदेव राय

72. Between whom did the battle of Talikota (Rakshas - Tangdi) take place तालीकोटा (राक्षस- टंगडी) का युद्ध किसके किसके बीच हुआ — Vijayanagara and the combined forces (Bijapur, Bijapur, Ahmednagar, Bidar)/ विजयनगर और संयुक्त सेना (बीजापुर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर)

73. Mahmud village was the revenue head of which dynasty? महमूद गाँवा किस वंश का राजस्व प्रमुख था? Bahmani dynasty /बहमनी वंश

74. How many invasions did Ahmad Shah Abdali make in India?/अहमदशाह अब्दाली ने भारत में कितने आक्रमण किये – seven (the first was Punjab in 1748)/सात (पहला 1748 में पंजाब)

75. Between whom did the 'Treaty of Jhalki' take place/'झलकी की संधि' किस-किस के मध्य हुई— between the Nizam of Hyderabad and Balaji Bajirao/हैदराबाद के निजाम एवं बाला जी बाजीराव के मध्य

76. During which Mughal rule, the third battle of Panipat (1761) and the battle of Buxar (1764) took place/किस मुगल शासन के काल में पानीपत का तृतीय युद्ध(1761) और बक्सर का युद्ध(1764) हुआ – Shah Alam II/शाहआलम द्वितीय

77. The war of Wandiwash (in 1760 AD) was fought between/वांडीवाश का युद्ध (1760 ई. में) किनके बीच लड़ा गया ?-British and French/अंग्रेज और फ्रांसिसी के

78. Fort William in India is situated on the bank of which river/भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है – हुगली

79. Who is the author of Prithviraj Vijay/पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है –Jayanak/जयनक

80. Who got the Mahabharata translated into Bengali/महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने करवाया था – Nusrat Shah/नुसरत शाह ने

INDIAN POLITY SPEICAL

SHIPRA CHAUHAN

Q1. In which of the following case/s the six rights guaranteed by article 19 can be suspended?

निम्नलिखित में से किस मामले में अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत छह अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है?

1. External Aggression /बाहरी आक्रमण
2. Internal Emergency /आंतरिक आपातकाल

- A. 1 only
- B. 2 only
- C. Both**
- D. None of these

Sol- The Constitution of India has provided for imposition of emergency caused by war, external aggression or internal rebellion.

This is described as the National Emergency.

This type of emergency can be declared by the President of India if he is satisfied that the situation is very grave and the security of India or any part thereof is threatened or is likely to be threatened either, by war or external aggression by armed rebellion within the country.

The declaration of National Emergency has effects both on the rights of individuals and the autonomy of the states.

The Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended and this suspension continues till the end of the emergency.

भारत के संविधान ने युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के कारण आपातकाल लगाने का प्रावधान किया है।

इसे राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में वर्णित किया गया है।

इस प्रकार के आपातकाल की घोषणा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है यदि वह संतुष्ट है कि स्थिति बहुत गंभीर है और भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है या खतरा होने की संभावना है, युद्ध या बाहरी आक्रमण द्वारा सशस्त्र विद्रोह द्वारा देश।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की स्वायत्तता दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और यह निलंबन आपातकाल के अंत तक जारी रहता है।

Q2. The protection under article 21 is:

अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा है:

- A. Against arbitrary legislative action /मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ
- B. Against arbitrary executive action /मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ
- C. Both A & B /ए और बी दोनों**
- D. None /कोई नहीं

Sol- Article 21 of Constitution of India: Protection of Life and Personal Liberty.

Article 21 states that “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law.”

Thus, article 21 secures two rights: Right to life, and Right to personal liberty.

The Supreme Court of India in the famous **Gopalan Case (1950)** held that protection under Article 21 is available only against arbitrary executive action and not against arbitrary legislative action.

It clarified that if personal liberty of an individual is taken away by a law, the validity of the law cannot be questioned. In the same case the Supreme Court held personal liberty would only mean liberty relating to the person or body of the individual.

However, in the Maneka Gandhi Case (1973) the Supreme Court overruled its judgement in the Gopalan Case by widely interpreting Article 21.

It stated that protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive action but also against arbitrary legislative action by introducing the American concept of 'due process of law'.

It pronounced the expression 'Personal Liberty' in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a wide range of rights that go to constitute the personal liberties of a man.

The court's decision in Maneka Gandhi Case has been reaffirmed in the subsequent cases. In the way of widening the implications of personal liberty, in 1993, the Supreme Court recognized primary education as a fundamental right under Article 21.

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"

इस प्रकार, अनुच्छेद 21 दो अधिकारों को सुरक्षित करता है: जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध गोपालन मामले (1950) में कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ।

इसने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा छीन लिया जाता है, तो कानून की वैधता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ केवल व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता होगी।

हालांकि, मेनका गांधी केस (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करके गोपालन मामले में अपने फैसले को खारिज कर दिया।

इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि 'कानून की उचित प्रक्रिया' की अमेरिकी अवधारणा को पेश करके मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होनी चाहिए।

इसने कहा कि अनुच्छेद 21 में 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' की अभिव्यक्ति व्यापक आयाम की है और इसमें अधिकारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करती है।

मेनका गांधी मामले में अदालत के फैसले की बाद के मामलों में पुष्टि की गई है। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निहितार्थ को व्यापक बनाने के लिए अनुच्छेद 21 के तहत प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।

Q3. Which of the following writs can be issued against administrative authorities?

निम्नलिखित में से कौन सा रिट प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है?

- A. Prohibition, Certiorari & Mandamus /निषेध, प्रमाणिकता और परमादेश
- B. Certiorari & Mandamus /उत्प्रेषण और परमादेश**
- C. Prohibition & Mandamus /निषेध और परमादेश
- D. Prohibition & Certiorari /निषेध और उत्प्रेषण

Sol- Prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities. It is not available against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies.

निषेध केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है।

Type of Writ	Meaning of the word	Purpose of Issue
Habeas Corpus	You may have the body	To release a person who has been detained unlawfully whether in prison or in private custody.
Mandamus	We Command	To secure the performance of public duties by lower court, tribunal or public authority.
Certiorari	To be certified	To quash the order already passed by an inferior court, tribunal or quasi judicial authority.
Prohibition	-	To prohibit an inferior court from continuing the proceedings in a particular case where it has no jurisdiction to try.
Quo Warranto	What is your authority?	To restrain a person from holding a public office which he is not entitled.

Q4. Which of the following articles are correctly matched:

निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही सुमेलित हैं:

1. Election Commission - Article 338 /चुनाव आयोग - अनुच्छेद 338
2. Finance Commission - Article 280 /वित्त आयोग - अनुच्छेद 280
3. National Commission for SCs - Article 324 /राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - अनुच्छेद 324
4. CAG - Article 148 /सीएजी - अनुच्छेद 148
5. Attorney General of India - Article 76 /भारत का महान्यायवादी - अनुच्छेद 76

A. All except 1 & 5

B. All except 1 & 3

C. All except 2 & 5

D. None of the above options are correct.

Sol-

The Election Commission of India (ECI) is an autonomous body under the ownership of Ministry of Law and Justice, Government of India. It is established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country. Article 324 deals with Election Commission.

Article 338 of the Indian constitution deals with National Commission for Scheduled Castes. Article 338 A deals with National Commission for Scheduled tribes.

भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक स्वायत्त निकाय है। यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सीधे भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है।

Q5. Which of the following Articles of the Constitution of India gives the right to Ministers and Attorney-General to speak in or to take part in the proceedings of either House of Parliament?

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार देता है?

- A. Article 84 /अनुच्छेद 84
- B. Article 85 /अनुच्छेद 85
- C. Article 87 /अनुच्छेद 87
- D. Article 88 /अनुच्छेद 88

Sol- Article 88 -

Rights of Ministers and Attorney General in respects Houses Every Minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote
Officers of Parliament

अनुच्छेद 88 -

सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा। जिसे वह सदस्य नामित किया जा सकता है, लेकिन इस अनुच्छेद के आधार पर संसद के अधिकारियों को वोट देने का हकदार नहीं होगा

Q6. Under which Article of the Indian Constitution has the State been empowered to protect and improve the environment, forests and wildlife?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार करने का अधिकार दिया गया है?

- A. Article 43-A /अनुच्छेद 43-ए
- B. Article 48-A /अनुच्छेद 48-ए
- C. Article 44 /अनुच्छेद 44
- D. Article 46 /अनुच्छेद 46

Sol- Article 43A. Participation of workers in management of industries. -The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way, to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry."

Article 48 -A of the constitution says that "the state shall endeavor to protect and improve the **environment** and to safeguard the forests and wild life of the country".

Article 44. Uniform civil code for the citizens The State shall endeavour to secure for the citizens a **uniform civil code** throughout the territory of India.

Article 46 "The State shall promote with special care the **educational and economic** interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

अनुच्छेद 43ए. उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। -राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा।"

संविधान का अनुच्छेद 48-ए कहता है कि "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 44. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 46 "राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय से बचाएगा। शोषण।"

Q7. Article 359 of the Constitution of India deals with which one of the following?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?

- A. Declaration of financial emergency /वित्तीय आपातकाल की घोषणा
- B. Promulgation of President's rule in a State /किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा
- C. Suspension of the enforcement of fundamental rights except a few during emergency /आपातकाल के दौरान कुछ को छोड़कर मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
- D. Terms and conditions of service of Members of the Union Public Service Commission /संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें

Sol-

- Suspension of other Fundamental Rights:
- Under Article 359, the President is authorised to suspend, by order, the right to move any court for the enforcement of Fundamental Rights during a National Emergency.
- Thus, remedial measures are suspended and not the Fundamental Rights.
- The suspension of enforcement relates to only those Fundamental Rights that are specified in the Presidential Order.
- The suspension could be for the period during the operation of emergency or for a shorter period.
- The Order should be laid before each House of Parliament for approval.
- The 44 Amendment Act mandates that the President cannot suspend the right to move the court for the enforcement of Fundamental Rights guaranteed by Article 20 and 21.

अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन:

अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबित करने का अधिकार है।

इस प्रकार, उपचारात्मक उपाय निलंबित हैं न कि मौलिक अधिकार।

प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मौलिक अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट हैं।

निलंबन आपातकाल के संचालन के दौरान या कम अवधि के लिए हो सकता है।

आदेश को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।

44वां संशोधन अधिनियम अनिवार्य करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते।

Q8. Which Article of the Constitution of India directs the State to make effective provision for securing the Right to work?
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम का अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है?

- A. Article 16 /अनुच्छेद 16
- B. Article 38 /अनुच्छेद 38
- C. Article 41 /अनुच्छेद 41
- D. Article 43 /अनुच्छेद 43

Sol-

Article 16 - Equality of opportunity in matters of public employment. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.

Article 38 - State to secure a social order for the promotion of welfare of the people

Article 43 - Living wage, etc, for workers The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co operative basis in rural areas

Article 41 - Right to work, to education and to public assistance in certain cases The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want

अनुच्छेद 16 - लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।

अनुच्छेद 38 - राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए

अनुच्छेद 43 - श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि, राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्यथा, काम, एक जीवित मजदूरी, काम की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। सभ्य जीवन स्तर और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद और, विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 41 - कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बेरोजगारी के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, बुढ़ापा, बीमारी और अपंगता, और अन्य मामलों में अवांछित आवश्यकता

Q9. Which one of the following Articles of the Constitution of India deals with the saving of laws giving effect to certain directive principles?

भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित है?

- A. Article 32 /अनुच्छेद 32

- B. Article 31-A /अनुच्छेद 31-ए
- C. Article 31-B /अनुच्छेद 31-बी
- D. Article 31-C /अनुच्छेद 31-सी**

Sol-

Article 31C was inserted by the 25th Amendment Act of 1971. It contained provisions related to the saving of laws giving effect to certain directive principles.

No law that seeks to implement all or any of the directive principles specified in Part IV shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 (equality before law and equal protection of laws) or Article 19 (protection of six rights in respect of speech, assembly, movement, etc.)

अनुच्छेद 31सी 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम द्वारा डाला गया था। इसमें कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत से संबंधित प्रावधान शामिल थे।

कोई भी कानून जो भाग IV में निर्दिष्ट सभी या किसी भी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करता है, अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा) या अनुच्छेद 19 (छह की सुरक्षा) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं होगा। भाषण, सभा, आंदोलन, आदि के संबंध में अधिकार)

Q10. If central government want to establish a new state. Which articles of constitution allows them to do?

यदि केंद्र सरकार नए राज्य की स्थापना करना चाहती है। संविधान के कौन से अनुच्छेद उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं?

- A. Article 1 /अनुच्छेद 1
- B. Article 2 /अनुच्छेद 2**
- C. Article 3 /अनुच्छेद 3
- D. Article 4 /अनुच्छेद 4

Sol-

Article 2 of the Constitution of India vests in the Indian Parliament the exclusive power to admit or establish new states into the Indian Union on such terms and conditions as the Parliament may provide for.

Article 1 – Name and territory of the union.

Article 3 – Formation of new states and alteration of areas, boundaries, and name of existing states.

भारत के संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को ऐसे नियमों और शर्तों पर भारतीय संघ में नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने की विशेष शक्ति प्रदान करता है जो संसद प्रदान कर सकती है।

अनुच्छेद 1 - संघ का नाम और क्षेत्र

अनुच्छेद 3 - नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन।

Q11. Recently Budget 2022 announced by the Finance Minister of India. Which article allow to do?

हाल ही में बजट 2022 भारत के वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया। कौन सा अनुच्छेद करने की अनुमति देता है?

- A. Article 110 /अनुच्छेद 110
- B. Article 108 /अनुच्छेद 108
- C. Article 112 /अनुच्छेद 112**
- D. Article 114 /अनुच्छेद 114

Sol-

According to Article 112 of the Indian Constitution, the Union Budget of a year, also referred to as the annual financial statement, is a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for that particular year. Union Budget is classified into Revenue Budget and Capital Budget.

Article 110 – Definition of “Money Bills”

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया गया है।

अनुच्छेद 110 - "धन विधेयक" की परिभाषा

Q12. Article 14 deals with Right to Equality, but the President or the Governor is not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of his office. Which article, is the exception to Article 19?

अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है, लेकिन राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19 का अपवाद है?

- A. Article 41 /अनुच्छेद 41
- B. Article 15 /अनुच्छेद 15
- C. Article 361 /अनुच्छेद 361
- D. Article 343 /अनुच्छेद 343

Sol-

Article 361 is an exception to Article 14 (Right to Equality) of the Indian Constitution. The features are as follows:

1. The President or the Governor is not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of his office.
2. No criminal proceedings shall be conducted against the President or the Governor during his term of office.
3. No arrest or imprisonment shall be made against the President or Governor during his term of office.
4. Civil proceedings in which relief is claimed against the President or the Governor shall be instituted during his term of office in any court in respect of any act done or purporting to be done by him in his personal capacity, whether before or after he entered his office as President or Governor until the expiration of two months next after notice is given to him in writing.

अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का अपवाद है। विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।
2. राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
3. राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी या कारावास नहीं किया जाएगा।
4. सिविल कार्यवाही जिसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ राहत का दावा किया जाता है, किसी भी अदालत में उनके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, चाहे वह प्रवेश करने से पहले या बाद में, किसी भी न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। उसे लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में उसका कार्यालय।

Q13. Under which article Supreme Court and High Courts respectively, both have power to issue certain writs?

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्रमशः किस अनुच्छेद के तहत कुछ रिट जारी करने की शक्ति है?

- A. Article 32 and Article 226 /अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
- B. Article 32 and Article 224 /अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 224
- C. Article 32 and Article 227 /अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 227

D. Article 32 and Article 233 /अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 233

Sol-

It is a legal document issued by the court that orders a person or entity to perform a specific act or to cease performing a specific action or deed.

In India, writs are issued by the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India and by the High Court under Article 226 of the Constitution of India.

यह अदालत द्वारा जारी किया गया एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति या संस्था को एक विशिष्ट कार्य करने या किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने से रोकने का आदेश देता है।

भारत में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाते हैं।

Q14. Under which article President and Governor respectively to grant pardon in certain cases?

किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल क्रमशः कुछ मामलों में क्षमादान देते हैं?

A. Article 71 and 161 /अनुच्छेद 71 और 161

B. Article 72 and 161 /अनुच्छेद 72 और 161

C. Article 73 and 163 /अनुच्छेद 73 और 163

D. Article 74 and 165 /अनुच्छेद 74 और 165

Sol-

Pardoning or giving mercy can be seen as a constitutional scheme too. In the Indian Constitution, this power to grant mercy is enjoyed under Article 72 and Article 161 by the President and the Governor, respectively.

क्षमा या दया देना एक संवैधानिक योजना के रूप में भी देखा जा सकता है। भारतीय संविधान में, दया देने की यह शक्ति क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त की जाती है।

Q15. Which article deals with Advocate General for the State?

कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है?

A. Article 166 /अनुच्छेद 166

B. Article 165 /अनुच्छेद 165

C. Article 167 /अनुच्छेद 167

D. Article 168 /अनुच्छेद 168

Sol-

Article 165: Advocate General for the State

The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed as a Judge of a High Court to be Advocate General for the State.

अनुच्छेद 165: राज्य के लिए महाधिवक्ता

प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, जो राज्य के लिए महाधिवक्ता हो।

Q16. Which article deals with the appointment of acting Chief justice?

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?

A. Article 123 /अनुच्छेद 123

B. Article 126 /अनुच्छेद 126

C. Article 148 /अनुच्छेद 148

D. Article 149 /अनुच्छेद 149

Sol-

Appointment of acting Chief Justice is to be made by the President under Article 126 of the Constitution.

The Chief Justice and Judges of the High Courts are to be appointed by the President under clause (1) of Article 217 of the Constitution.

संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जानी है।

Q17. Which article deals with the election of President?

राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?

- A. Article 52 /अनुच्छेद 52
- B. Article 53 /अनुच्छेद 53
- C. Article 54 /अनुच्छेद 54
- D. Article 55 /अनुच्छेद 55

Sol-

The manner of election of President is provided by Article 55 of the constitution. Each elector casts a different number of votes. The general principle is that the total number of votes cast by Members of parliament equals the total number of votes cast by State Legislators.

राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका संविधान के अनुच्छेद 55 द्वारा प्रदान किया गया है। प्रत्येक मतदाता अलग-अलग वोट डालता है। सामान्य सिद्धांत यह है कि संसद सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या राज्य के विधायकों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या के बराबर होती है।

Q18. Which of the following is incorrect match?

निम्नलिखित में से कौनसा गलत मिलान है?

- A. Article 74 – Council of ministers to aid and advise President /राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
- B. Article 79 – Constitution of Parliament /संसद का संविधान
- C. Article 214 – High Courts for states /राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- D. Article 267 – Consolidated Fund and Public Accounts Fund /संचित निधि और लोक लेखा निधि

Sol-

Article 266 – Consolidated Fund and Public Accounts Fund

Article 267 – Contingency Fund of India

अनुच्छेद 266 – संचित निधि और लोक लेखा निधि

अनुच्छेद 267 – भारत की आकस्मिकता निधि

Q19. Which article deals with Right to property?

संपत्ति के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है?

- A. Article 300 A /अनुच्छेद 300 ए
- B. Article 343 /अनुच्छेद 343
- C. Article 352 /अनुच्छेद 352
- D. Article 356 /अनुच्छेद 356

Sol-

Article 343 – Official languages of the Union

Article 352 – Proclamation of emergency (National Emergency)

Article 356 – State Emergency (President's Rule)

Article 360 – Financial Emergency

अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषाएँ

अनुच्छेद 352 – आपातकाल की उद्घोषणा (राष्ट्रीय आपातकाल)

अनुच्छेद 356 – राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)

अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल

Q20. Which article deals with Special provision with respect to the State of Nagaland?

कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है?

A. Article 371 /अनुच्छेद 371

B. Article 371 A /अनुच्छेद 371 ए

C. Article 372 /अनुच्छेद 372

D. Article 371 J /अनुच्छेद 371 जे

Sol-

Article 371 A – Special provision with respect to the State of Nagaland

Article 371 J – Special Status for Hyderabad–Karnataka region

अनुच्छेद 371 ए – नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद 371 जे - हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा

Q21. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution?

निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला?

A. British Constitution /ब्रिटिश संविधान

B. US Constitution /अमेरिकी संविधान

C. Irish Constitution /आयरिश संविधान

D. The Government of India Act, 1935 /भारत सरकार अधिनियम, 1935

Sol-

Government of India Act, 1935 had the most profound influence on the constitutional provision.

The Government of India Act, 1935 was an Act adapted from the Parliament of the United Kingdom. It originally received royal assent in August 1935.

It was the longest Act of (British) Parliament ever enacted until Greater London Authority Act 1999 surpassed it.

It was divided into two separate acts namely, the Government of India Act 1935 and the Government of Burma Act 1935.

The Act was based on:

- Simon Commission Report
- The recommendations of the Round Table Conferences
- The White Paper published by the British government in 1933 (based on the Third Round Table Conference)
- Report of the Joint Select Committees.

This Act divided powers between the centre and the provinces.

There were three lists which gave the subjects under each government.

- Federal List (Centre)
- Provincial List (Provinces)
- Concurrent List (Both)

The Viceroy was vested with residual powers.

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का संवैधानिक प्रावधान पर सबसे गहरा प्रभाव था।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 यूनाइटेड किंगडम की संसद से अनुकूलित एक अधिनियम था। इसे मूल रूप से अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति मिली थी। ग्रेटर लंदन अथॉरिटी एक्ट 1999 को पार करने तक यह (ब्रिटिश) संसद का अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था।

इसे दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935।

अधिनियम पर आधारित था:

- साइमन कमीशन की रिपोर्ट
- गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशें
- 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र (तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर आधारित)
- संयुक्त प्रवर समितियों की रिपोर्ट।

इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया।

तीन सूचियाँ थीं जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों को देती थीं।

- संघीय सूची (केंद्र)
- प्रांतीय सूची (प्रांत)
- समवर्ती सूची (दोनों)

वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त थीं।

Features
Provincial autonomy
Diarchy at the centre
Bicameral legislature
Federal court
Indian Council
Franchise
Reorganisation

Q22. The first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through:

भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किया गया था:

- Indian Council Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
- Indian Council Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- Indian Council Act, 1909 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

D. Government of India Act, 1919 /भारत सरकार अधिनियम, 1919

Sol-

The Indian Councils Act 1861 was an Act of the Parliament of the United Kingdom that transformed India's executive council to function as a cabinet run on the portfolio system.

The Indian Council Act, 1861 made a beginning of representative institutions by associating Indians with the law-making process.

It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council.

In 1862, Lord Canning, the then viceroy, nominated three Indians to his legislative council—the Raja of Benaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.

The Indian Councils Act 1892 was an Act of British Parliament that introduced various amendments to the composition and function of legislative councils in British India. Most notably, the act expanded the number of members in the central and provincial councils.

The Indian Councils Act 1909, commonly known as the Morley–Minto or Minto–Morley Reforms, was an act of the Parliament of the United Kingdom that brought about a limited increase in the involvement of Indians in the governance of British India.

The Government of India Act 1919 was an Act of the Parliament of the United Kingdom. It was passed to expand participation of Indians in the government of India. The Act embodied the reforms recommended in the report of the Secretary of State for India, Edwin Montagu, and the Viceroy, Chelmsford. The Act covered ten years, from 1919 to 1929

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर चलने वाले कैबिनेट के रूप में कार्य करने के लिए बदल दिया।

The Indian Council Act, 1861 made a beginning of representative institutions by associating Indians with the law-making process.

It thus provided that the viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council.

In 1862, Lord Canning, the then viceroy, nominated three Indians to his legislative council—the Raja of Benaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.

भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए। सबसे विशेष रूप से, अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया।

भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे आमतौर पर मॉर्ले-मिंटो या मिंटो-मॉर्ले सुधार के रूप में जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि की।

भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था। यह भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव, एडविन मोंटेग्यू और वाइसराय, चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। इस अधिनियम में 1919 से 1929 तक दस वर्ष शामिल थे।

Q23. The instrument of instructions contained in the Government of India Act, 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित निर्देशों के उपकरण को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था

- A. Fundamental Rights /मौलिक अधिकार
- B. Directive Principles of the State Policy/राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत**
- C. Fundamental Duties /मौलिक कर्तव्य
- D. Emergency Provisions /आपातकालीन प्रावधान

Sol-

The Directive Principles resemble the 'Instrument of Instructions' enumerated in the Government of India Act of 1935.

In the words of Dr. B.R. Ambedkar, 'the Directive Principles are like the instrument of instructions, which were issued to the Governor-General and to the Governors of the colonies of India by the British Government under the Government of India Act of 1935.

What is called Directive Principles is merely another name for the instrument of instructions.

The only difference is that they are instructions to the legislature and the executive'.

निर्देशक सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन' से मिलते जुलते हैं।

डॉ. बी.आर. के शब्दों में अम्बेडकर के अनुसार, 'निदेशक सिद्धांत निर्देश के साधन की तरह हैं, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल और भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों को जारी किए गए थे।

जिसे निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, वह निर्देश के साधन का ही दूसरा नाम है।

अंतर केवल इतना है कि वे विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश हैं।

Q24. With reference to the colonial period of India, the trade monopoly of the East India Company was ended by भारत के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया

- A. The Regulating Act of 1773 /1773 का विनियमन अधिनियम
- B. Pitt's India Act of 1784 /पिट का भारत अधिनियम 1784
- C. The Charter Act of 1813 /1813 का चार्टर एक्ट**
- D. The Charter Act of 1833 /1833 का चार्टर एक्ट

Sol-

The Regulating Act of 1773 was an Act of the Parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company's rule in India.

The Pitt's India Act in 1784, also known as the East India Company Act, was passed in British Parliament to correct the defects of the previously signed Regulating Act in 1773. The Regulating Act in 1773 was an Act of the Parliament of Great Britain that's purpose was to overhaul the management of the East India Company's rule in India. The Act proved to not be a long-term solution.

The East India Company Act 1813, also known as the Charter Act 1813, was an Act of the Parliament of the United Kingdom which renewed the charter issued to the British East India Company, and continued the Company's rule in India. The Charter Act of 1813 ended the commercial trade monopoly of the East India Company except for trade in tea and trade with China.

The Charter Act of 1833 was passed in the British Parliament which renewed the East India Company's charter for another 20 years. This was also called the Government of India Act 1833 or the Saint Helena Act 1833. The company's commercial activities were closed down.

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को बदलना था।

1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, 1773 में पहले से हस्ताक्षरित रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन को ओवरहाल करना था। अधिनियम एक दीर्घकालिक समाधान नहीं साबित हुआ।

ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813, जिसे चार्टर अधिनियम 1813 के रूप में भी जाना जाता है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीनीकरण किया और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया।

1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1833 या सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहा जाता था। कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया था।

Q25. In which year did the Parliament adopt Indian Constitution?

संसद ने किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया?

- A. 1947
- B. 1948
- C. 1950
- D. 1952

Sol-

India, also known as Bharat, is a Union of States. It is a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic with a parliamentary system of government.

The Republic is governed in terms of the Constitution of India which was adopted by the Constituent Assembly on 26th November, 1949 and came into force on 26th January, 1950.

भारत, जिसे भारत के नाम से भी जाना जाता है, राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है।

गणतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ था।

Q26. The Supreme Court of India was set up by the

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था

- A. Regulating Act, 1773 / रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
- B. Pitt's India Act, 1784 / पिट का भारत अधिनियम, 1784
- C. Charter Act, 1813 / चार्टर अधिनियम, 1813
- D. Charter Act, 1833 / चार्टर अधिनियम 1833

Sol-

The Supreme Court of Judicature at Fort William in Calcutta (Kolkata), was founded in 1774 by the Regulating Act of 1773.

It replaced the Mayor's Court of Calcutta and was British India's highest court from 1774 until 1862, when the High Court of Calcutta was established by the Indian High Courts Act 1861.

कलकत्ता (कोलकाता) में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा की गई थी।

इसने कलकत्ता के मेयर कोर्ट को बदल दिया और 1774 से 1862 तक ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जब भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा कलकत्ता का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था।

Q27. The power of Supreme Court to decide in case of a dispute between two or more state is called
दो या अधिक राज्य के बीच विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कहा जाता है

- A. Original jurisdiction/ आरंभिक अधिकारिता
- B. Writ Jurisdiction/रिट अधिकारिता
- C. Appellate Jurisdiction/अपील न्यायिक क्षेत्र
- D. Advisory jurisdiction/सलाहकार क्षेत्राधिकार

Sol-

In India, the Supreme Court has original, appellate and advisory jurisdiction. Its exclusive original jurisdiction extends to all cases between the Government of India and the States of India or between Government of India and states on one side and one or more states on other side or cases between different states.

A person whose right is infringed by an arbitrary administrative action may approach the Court for appropriate remedy. The Constitution of India, under Articles 32 and 226 confers writ jurisdiction on Supreme Court and High Courts, respectively for enforcement/protection of fundamental rights of an Individual.

The power of the higher court to review the decision or change the result of the decisions made by the lower courts is called appellate jurisdiction. The Supreme Court in India is the highest court of order in the country. It can hear appeals in cases like civil cases and criminal cases.

Advisory Jurisdiction is when a lower court or any constitutional body seeks the advice of the higher Court in a matter of law.

भारत में, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं। इसका अनन्य मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और भारत के राज्यों के बीच या एक तरफ भारत सरकार और राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच के मामलों तक फैला हुआ है।

एक व्यक्ति जिसका अधिकार एक मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा उल्लंघन किया गया है, उचित उपचार के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन/संरक्षण के लिए क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को रिट क्षेत्राधिकार प्रदान करता है।

निर्णय की समीक्षा करने या निचली अदालतों द्वारा किए गए निर्णयों के परिणाम को बदलने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। यह दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों जैसे मामलों में अपील सुन सकता है।

सलाहकार क्षेत्राधिकार तब होता है जब कोई निचली अदालत या कोई संवैधानिक निकाय कानून के मामले में उच्च न्यायालय की सलाह लेता है।

Q28. Central Information Commission falls under the _____.

केन्द्रीय सूचना आयोग _____ के अंतर्गत आता है।

- A. Ministry of Personnel and training/कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय

- B. Ministry of Home Affairs/गृह मंत्रालय
- C. Prime Minister's Office/प्रधान मंत्री कार्यालय
- D. Law Ministry/कानून मंत्रालय

Sol-

The Central Information Commission (CIC) is a statutory body, set-up under the Right to Information Act in 2005. The Commission includes one Chief Information Commissioner and not more than 10 information commissioners who are appointed by the President of India.

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Q29. The process of Constitutional amendment in India is taken from _____ .

भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया _____ से ली गई है।

- A. America/अमेरिका
- B. Japan/जापान
- C. South Africa/दक्षिण अफ्रीका
- D. Canada/कनाडा

Sol-

United States of America

1. Impeachment of the president
2. Functions of president and vice-president
3. Removal of Supreme Court and High court judges
4. Fundamental Rights
5. Judicial review
6. Independence of judiciary
7. The preamble of the constitution

Japan

1. Concept of “procedure established by Law”

South Africa

1. Election of members of the Rajya Sabha
2. Amendment of the Constitution

Canada

1. Centrifugal form of federalism where the centre is stronger than the states.
2. Residuary powers vest with the centre
3. Centre appoints the Governors at the states
4. Advisory jurisdiction of the supreme court

संयुक्त राज्य अमरीका

1. राष्ट्रपति का महाभियोग

2. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य
3. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना
4. मौलिक अधिकार
5. न्यायिक समीक्षा
6. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
7. संविधान की प्रस्तावना

जापान

1. "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की अवधारणा

दक्षिण अफ्रीका

1. राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
2. संविधान का संशोधन

कनाडा

1. संघवाद का केंद्रापसारक रूप जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत होता है।
2. अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं
3. केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है
4. सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार

Q30. The idea of including the Emergency provisions in the Constitution of India has been borrowed from the भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने के विचार से उधार लिया गया है

- A. Constitution of Canada /कनाडा का संविधान
- B. Weimar Constitution of Germany /जर्मनी का वीमर संविधान**
- C. Constitution of Ireland /आयरलैंड का संविधान
- D. Constitution of USA /संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान

Sol-

Ireland

1. Directive Principles of State Policy
2. Method of Election of the president
3. Members nomination to the Rajya Sabha by the President

Germany

1. Fundamental Rights are suspended during Emergency

आयरलैंड

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
2. राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
3. राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन

जर्मनी

1. आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है

Q31. What can be the maximum number of members in a legislative assembly of a state in India?

भारत के किसी राज्य की विधान सभा में अधिकतम सदस्य कौन-से हो सकते हैं?

- A. 400
- B. 500**
- C. 450
- D. 550

Sol-

The Constitution of India states that a State Legislative Assembly must have no less than 60 and no more than 500 members however an exception may be granted via an Act of Parliament as is the case in the states of Goa, Sikkim, Mizoram and the union territory of Puducherry which have fewer than 60 members.

भारत के संविधान में कहा गया है कि एक राज्य विधान सभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, हालांकि गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अपवाद दिया जा सकता है। पुडुचेरी जिसमें 60 से कम सदस्य हैं।

Q32. What was the number of state in India after the States Reorganization Act 1956, which reorganized the boundaries of different states on linguistic basis?

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में राज्य की संख्या क्या थी, जिसने भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों की सीमाओं को पुनर्गठित किया?

- A. 13
- B. 14**
- C. 15
- D. 20

Sol-

After the creation of the Andhra state in 1953, other linguistic communities also demanded their own separate states.

The central government appointed a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of states.

The States Reorganisation Act was passed in 1956 and it led to the creation of 14 states and six union territories.

The commission recommended the redrawing of the district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada, and Telugu speakers respectively.

The death of Potti Sriramulu after fifty-six days hunger strike demanding a separate state of Andhra leads to the formation of the states Reorganization Act, 1956.

The States Reorganisation Act, 1956 drastically redrew the boundaries of states and territories in India, organizing them along linguistic lines.

Andhra is the first state formed on a linguistic basis in India.

Andhra state was formed on 1st October 1953.

Andhra was changed to Andhra Pradesh in 1956.

1953 में आंध्र राज्य के निर्माण के बाद, अन्य भाषाई समुदायों ने भी अपने अलग राज्यों की मांग की।

केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसके कारण 14 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ।

आयोग ने क्रमशः असमिया, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के कॉम्पैक्ट प्रांत बनाने के लिए जिले और प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने की सिफारिश की।

पोट्टी श्रीरामलु की मृत्यु के बाद छप्पन दिनों की भूख हड़ताल के बाद अलग आंध्र राज्य की मांग के कारण राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का गठन हुआ।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को भाषाई आधार पर व्यवस्थित करते हुए काफी हद तक कम कर दिया। आंध्र भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है।

आंध्रा राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था।

1956 में आंध्रा को बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया।

Q33. Who called the Governor of a state as “federal fireman”?

किसने राज्य के गवर्नर को "संघीय फायरमैन" कहा?

- A. K T Shah /के टी शाह
- B. B R Ambedkar /बी आर अम्बेडकर
- C. C Rajagopalachari /सी राजगोपालाचारी
- D. Dr. Rajendra Prasad /डॉ. राजेंद्र प्रसाद

Sol-

C. Rajagopalachari (Rajaji) said that governor is like a federal fireman. Like fireman, they should only be called upon in case of emergency. Governor's office should not be used for party politics.

सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) ने कहा कि राज्यपाल एक संघीय फायरमैन की तरह है। फायरमैन की तरह, उन्हें केवल आपात स्थिति में ही बुलाया जाना चाहिए। राज्यपाल के कार्यालय का इस्तेमाल दलगत राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

Q34. Which amendment of the constitution added Administrative Tribunals?

संविधान के किस संशोधन ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को जोड़ा?

- A. 42nd amendment act /संशोधन अधिनियम
- B. 44th amendment act/संशोधन अधिनियम
- C. 46th amendment act/संशोधन अधिनियम
- D. 49th amendment act/संशोधन अधिनियम

Sol-

The 42nd Amendment changed the description of India from a "sovereign democratic republic" to a "sovereign, socialist secular democratic republic", and also changed the words "unity of the nation" to "unity and integrity of the nation".

Since the 42nd Amendment Act is the most comprehensive amendment of the Indian Constitution, called the 'Mini-Constitution'.

44th Amendment Act provided that the President can declare a national emergency only on the written recommendation of the cabinet. It is also one of the important amendments in the Indian Constitution, enacted by the Janata Government.

The 46th Amendment of the Constitution made it possible for the State to levy sales Tax on the price of the goods and materials used in works contracts as if there was a sale of such goods and materials.

42वें संशोधन ने भारत के वर्णन को "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" में बदल दिया, और "राष्ट्र की एकता" शब्दों को "राष्ट्र की एकता और अखंडता" में भी बदल दिया।

चूंकि 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे 'मिनी-संविधान' कहा जाता है।

44वें संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह जनता सरकार द्वारा अधिनियमित भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है।

संविधान के 46वें संशोधन ने राज्य के लिए कार्य अनुबंधों में प्रयुक्त वस्तुओं और सामग्रियों की कीमत पर बिक्री बिक्री कर लगाना संभव बना दिया जैसे कि ऐसी वस्तुओं और सामग्रियों की बिक्री हुई हो।

Q35. In which case, Supreme Court held that Preamble is integral part of the constitution?

किस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है?

- A. SR Bommai Case /एसआर बोम्माई केस
- B. Kesavanand Bharti Case /केसवानंद भारती केस
- C. Ashok Kumar Thakur Case /अशोक कुमार ठाकुर केस
- D. M C Mehta Case /एम सी मेहता केस

Sol-

Para 248 of the S.R. Bommai vs Union Of India (1994) judgement reads:

The preamble of the Constitution is an integral part of the Constitution.

Democratic form of Government, federal structure, unity and integrity of the nation, secularism, socialism, social justice and judicial review are basic features of the Constitution.

In the LIC of India case (1995) also, Supreme Court again held that the Preamble is an integral part of the Constitution of India.

एस.आर. का पैरा 248 बोम्माई बनाम भारत संघ (1994) का निर्णय पढ़ता है:

संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषताएं हैं।

एलआईसी ऑफ इंडिया मामले (1995) में भी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है।

Q36. How many times the word "Secular" appears in our constitution?

हमारे संविधान में "सेक्युलर" शब्द कितनी बार है?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Sol-

The term "secular" appears twice in Indian Constitution, first in Preamble and then in Article 25 (a).

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द भारतीय संविधान में दो बार आता है, पहले प्रस्तावना में और फिर अनुच्छेद 25 (ए) में।

Q37. On whose recommendation the President dissolves the Lok Sabha

किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है??

- A. Election Commission /चुनाव आयोग
- B. Rajya Sabha /राज्यसभा
- C. Chief Justice of India /भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D. Cabinet /मंत्रिमंडल

Sol-

The Lok Sabha which is also called the house of people in the lower house of the Indian parliament. The Lok Sabha is run by the representatives who are directly elected by the people.

Prime Minister is directly elected by the people. The president has to dissolve the Lok Sabha on the orders of the Prime Minister.

लोकसभा जिसे भारतीय संसद के निचले सदन में लोगों का घर भी कहा जाता है। लोकसभा का संचालन उन प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जो सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के आदेश पर लोकसभा को भंग करना होता है।

Q38. After how many days of absence from Parliament without permission can a M.P. be disqualified?

बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद एक एम.पी. अयोग्य हो जाता है?

A. 30 days /दिन

B. 60 days/दिन

C. 90 days/दिन

D. 120 days/दिन

Sol-

The Chairman or Speaker can declare the seat vacated if a member has remained absent from all its meetings for a period of 60 days without permission. While calculating the 60 days, the period for which the house is prorogued or adjourned is not counted.

अध्यक्ष या अध्यक्ष सीट को खाली घोषित कर सकते हैं यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि के लिए अपनी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। 60 दिनों की गणना करते समय, जिस अवधि के लिए सदन का सत्रावसान या स्थगित किया जाता है, उसकी गणना नहीं की जाती है।

Q39. Right to the enjoyment of pollution free water as interpreted by the Supreme Court in Subhas Kumar Vs. State of Bihar (1991) falls under,

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई प्रदूषण मुक्त जल के आनंद का अधिकार बिहार राज्य (1991) के अंतर्गत आता है

A. Right to Equality /समानता का अधिकार

B. Right to Liberty /स्वतंत्रता का अधिकार

C. Right against Exploitation /शोषण के खिलाफ अधिकार

D. Right to Life and Personal liberty /जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

Sol-

In Subhash Kumar Vs State of Bihar, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under article 21 of the constitution and it includes the right to the enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life.

If anything endangers or impairs that quality of life in derogation of laws, a citizen has recourse to article 32 of the constitution for removing the pollution of water or air which may be detrimental to the quality of life.

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें जीवन के पूर्ण आनंद के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है।

यदि कोई चीज कानूनों के अपमान में जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालती है या बिगाड़ती है, तो एक नागरिक को पानी या वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेना पड़ता है जो जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकता है।

Q40. The Indian Constitution is divided into

भारतीय संविधान विभाजित है

- A. 6 chapter /अध्याय
- B. 22 chapter /अध्याय**
- C. 24 chapter/अध्याय
- D. 25 chapter/अध्याय

Sol-

The Constitution of India is the most bulkiest Constitution in the world. Primarily, it had 395 Articles divided into 22 parts and 8 schedules. Now it has 448 articles divided into 25 parts and 12 schedules.

भारत का संविधान दुनिया का सबसे भारी संविधान है। मुख्य रूप से इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित थे। अब इसमें 448 लेख हैं जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित हैं।

Q41. According to the National Security Act of 1980 what is the maximum period of detention?

1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार नजरबंदी की अधिकतम अवधि क्या है?

- A. 3 months /महीने
- B. 5 months /महीने
- C. 10 months /महीने
- D. 12 months /महीने**

Sol-

The maximum period of detention is 12 months. The order can also be made by the District Magistrate or a Commissioner of Police under their respective jurisdictions, but the detention should be reported to the State Government along with the grounds on which the order has been made.

नजरबंदी की अधिकतम अवधि 12 महीने है। आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में भी दिया जा सकता है, लेकिन हिरासत की सूचना राज्य सरकार को उन आधारों के साथ दी जानी चाहिए जिन पर आदेश दिया गया है।

Q42. The chairman of Union Public Service Commission submits his resignation to?

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा किसको सौंपा?

- A. Chief Justice of India /भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B. President /राष्ट्रपति**
- C. Vice-President /उपाध्यक्ष
- D. Prime Minister /प्रधान मंत्री

Sol-

The terms and conditions of service of chairman and members of the Commission are governed by the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969.

The chairman and any other member of the Commission can submit his resignation at any time to the President of India.

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 द्वारा शासित होती हैं।

आयोग का अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर सकता है।

Q43. Which amendment made it compulsory for the president to give his assent to a Constitutional Amendment Bill?

किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया?

- A. 24th Amendment, 1971 /24वां संशोधन, 1971**
- B. 42nd Amendment, 1976 /42वां संशोधन, 1976

C. 44th Amendment, 1978 /44वां संशोधन, 1978

D. 69th Amendment, 1991 /69वां संशोधन, 1991

Sol-

24th amendment made it mandatory for the President to give his assent to the Constitutional Amendment bills.

It came into existence on 5th November 1971.

The 24th amendment increased the power of the parliament to amend Fundamental Rights.

Parliament can amend the constitution under Article 368 without changing the "Basic Structure of Doctrine".

The 69th Constitutional Amendment Act of 1991 gave the UT of Delhi special status, renamed it the National Capital Territory of Delhi, and named the Lieutenant Governor of Delhi as its administrator (LG).

24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।

यह 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया।

24वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बढ़ा दिया।

संसद "सिद्धांत की मूल संरचना" को बदले बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है।

1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया और दिल्ली के उपराज्यपाल को इसके प्रशासक (एलजी) के रूप में नामित किया।

Q44. Which of the following bills the Governor cannot return back for the reconsideration of the state legislature?

निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौट सकता है?

A. Constitutional Amendment Bill /संविधान संशोधन विधेयक

B. Money Bill /धन विधेयक

C. Ordinary Bill /साधारण विधेयक

D. Finance Bill /वित्त विधेयक

Sol-

After a bill is passed by the state legislature and sent to the Governor, he can return the bill for the reconsideration of the state legislature except the money bill.

राज्य विधायिका द्वारा एक विधेयक पारित होने और राज्यपाल को भेजे जाने के बाद, वह धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर सकता है।

Q45. Which of the following method is used for election of President in India?

भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?

A. Open Ballot System /ओपन बैलेट सिस्टम

B. Single Transferable Vote System /एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली

C. Direct Election /प्रत्यक्ष चुनाव

D. None of the above /इनमें से कोई भी नहीं

Sol-

In India, there are two methods of elections which are territorial representation and system of proportional representation. Proportional representation is further divided into single transferable vote system and list system.

Under this system, all sections of people get representation in proportion to their number i.e., even the smallest section of the population get its share of representation in the legislature.

The proportional representation by single transferable vote system is adopted for the election of President, Vice- President, and members to the Rajya Sabha.

भारत में, चुनाव के दो तरीके हैं जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को आगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली में विभाजित किया गया है।

इस प्रणाली के तहत, लोगों के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी आबादी के सबसे छोटे वर्ग को भी विधायिका में प्रतिनिधित्व का हिस्सा मिलता है।

एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अपनाया जाता है।

Q46. Who decides the salary and allowances of the Prime Minister?

प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है

- A. By Parliament /संसद द्वारा
- B. By Lok Sabha /लोकसभा द्वारा
- C. By Rajya Sabha /राज्यसभा द्वारा
- D. By Council of Ministers /मंत्रिपरिषद द्वारा

Sol-

The Parliament decides the salary and perquisites of the Prime Minister of India and of that of the MP's. The salary is further revised from time to time as mentioned under Article 75(6) of the Indian Constitution.

संसद भारत के प्रधान मंत्री और सांसदों के वेतन और अनुलाभों का फैसला करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(6) के तहत वेतन को समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

Q47. Who is the Guardian of the Fundamental Rights of the citizens of India?

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है?

- A. Parliament /संसद
- B. Judiciary /न्यायतंत्र
- C. Executive /कार्यकारी
- D. President /राष्ट्रपति

Sol-

The Supreme Court is a central authority body and is responsible for the protection of citizens Fundamental rights.

सुप्रीम कोर्ट एक केंद्रीय प्राधिकरण निकाय है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

Q48. In which case the Supreme Court laid down the doctrine of 'Basic Structure'?

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' का सिद्धांत निर्धारित किया?

- A. Indira Nehru Gandhi case /इंदिरा नेहरू गांधी मामला
- B. Minerva Mills case /मिनर्वा मिल्स मामला
- C. Central Coal Fields Ltd. Case /सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड मामला
- D. Kesavananda Bharati case /केशवानंद भारती मामला

Sol-

It was developed by the Supreme Court of India in a series of constitutional law cases in the 1960s and 1970s that culminated in Kesavananda Bharati v. State of Kerala, where the doctrine was formally adopted.

इसे 1960 और 1970 के दशक में संवैधानिक कानून के मामलों की एक श्रृंखला में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया था, जिसकी परिणति केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुई, जहाँ सिद्धांत को औपचारिक रूप से अपनाया गया था।

Q49. The procedure of Impeachment of the President of India is _____.

भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया _____ है।

- A. Judicial Procedure /न्यायिक प्रक्रिया
- B. Quasi - Judicial Procedure /अर्ध - न्यायिक प्रक्रिया**
- C. Legislative Procedure /विधायी प्रक्रिया
- D. Executive Procedure /कार्यकारी प्रक्रिया

Sol-

- The process of impeachment is quasi-judicial, which means that there must be a special majority of two-thirds members present and voting of both the houses and before this an investigation is set up by the other party.
- The impeachment charges are signed by one-fourth of the members of the Lok Sabha.
- A 14-day notice is given to the President of India. Then, Lok Sabha passes the impeachment charges with the two-thirds majority and sends it to Rajya Sabha.
- Then, Rajya Sabha investigates the charges.
- While Rajya Sabha is investigating the charges, the President has the right to sit in the proceedings.
- Rajya Sabha agrees to the charges and passes it with a two-thirds majority and the President is removed.

महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक है, जिसका अर्थ है कि दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए और इससे पहले दूसरे पक्ष द्वारा एक जांच स्थापित की जाती है।

महाभियोग के आरोपों पर लोकसभा के एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं।

भारत के राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। फिर, लोकसभा दो-तिहाई बहुमत के साथ महाभियोग के आरोपों को पारित करती है और इसे राज्यसभा को भेजती है।

फिर, राज्यसभा आरोपों की जांच करती है।

जबकि राज्यसभा आरोपों की जांच कर रही है, राष्ट्रपति को कार्यवाही में बैठने का अधिकार है।

राज्य सभा आरोपों से सहमत होती है और इसे दो-तिहाई बहुमत से पारित करती है और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है।

Q50. In which Schedule of the Constitution of India is the list of States and Union Territories given?

भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है?

- A. First Schedule /पहली अनुसूची**
- B. Second Schedule /दूसरी अनुसूची
- C. Fourth Schedule /चौथी अनुसूची
- D. Sixth Schedule /छठी अनुसूची

Sol-

First schedule contains the list of states and union territories. Indian constitution has 12 schedules.

पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।

Q 51. In which part of the Indian Constitution, are centre-state relations mentioned?

भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र-राज्य संबंधों का उल्लेख है?

- A. Part XI (Article 245 to 263) /भाग XI (अनुच्छेद 245 से 263)**
- B. Part IV (Article 36 to 51) /भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51)

- C. Part X (Article 244 to 244A) /भाग X (अनुच्छेद 244 से 244ए)
 D. Part XIII (Article 301 to 307) /भाग XIII (अनुच्छेद 301 से 307)

Sol-

India is a "Union of States" according to the Constitution of India.

Center-state relation is mentioned in Part XI of the constitution.

It divides into the legislative, executive, and financial powers between the centre and the states.

The centre-state relations are divided into three parts -

Legislative Relations (Article 245-255)

Administrative Relations (Article 256-263)

Financial Relations (Article 268-293)

भारत के संविधान के अनुसार भारत एक "राज्यों का संघ" है।

संविधान के भाग XI में केंद्र-राज्य संबंध का उल्लेख है।

यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों में विभाजित है।

केंद्र-राज्य संबंधों को तीन भागों में बांटा गया है -

विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255)

प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263)

वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 268-293)

Parts of the Constitution

Part	Articles	Areas
I	1-4	The Union & its Territories
II	5-11	Citizenship
III	12-35	Fundamental Rights
IV	36-51	Directive Principles of State Policy
IV A	51A	Fundamental Duties (42 nd Amendment)
V	52-151	The Union Government
VI	152-237	The State Government
VII	238	Dealt with states in Part B of the First Schedule. Repealed in 1956 by the Seventh Amendment.
VIII	239-241	Union Territories. Article 242 repealed.
IX	243 A-O	The Panchayats
IX-A	243 P-ZG	The Municipalities
X	244-244 A	The Scheduled & Tribal Areas
XI	245-263	Relations between the Union & the States
XII	264-300A	Finance, Property, Contracts & Suits
XIII	301-307	Trade, Commerce & Intercourse within the territory of India
XIV	308-323	Services under the Union & the States
XIV A	323A-323B	Administrative Tribunals (42 nd Amendment 1976)
XV	324-329	Elections
XVI	330-342	Special Provisions (Reservations of SC, ST, Anglo Indian etc)
XVII	343-351	Official Language
XVIII	352-360	Emergency Provisions
XIX	361-367	Miscellaneous Provisions (Immunity of President, Legislature etc)
XX	368	Amendment of the Constitution
XXI	369-392	Temporary, Transitional & Special Provision
XXII	393-395	Short Title, Commencement, Authoritative

Q52. _____ was the first Chief Election Commissioner of India.

_____ भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।

- A. Sunil Arora /सुनील अरोड़ा
- B. Sukumar Sen /सुकुमार सेन
- C. T N Seshan /टी एन शेषन
- D. M S Gill /एम एस गिल

Sol-

Sukumar Sen (civil servant) Sukumar Sen (2 January 1898 – 13 May 1963) was an Indian civil servant who was the first Chief Election Commissioner of India, serving from 21 March 1950 to 19 December 1958.

सुकुमार सेन (सिविल सेवक) सुकुमार सेन (2 जनवरी 1898 - 13 मई 1963) एक भारतीय सिविल सेवक थे, जो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।

Q53. Which was the first state to introduce NOTA in elections?

चुनाव में नोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था?

- A. Punjab /पंजाब
- B. Himachal Pradesh /हिमाचल प्रदेश
- C. Chhattisgarh /छत्तीसगढ़
- D. Goa /गोवा

Sol-

- NOTA is the negative vote that any citizen can cast if he/she is not satisfied with any of the candidates.
- NOTA made legal on 27th September 2013.
- France is the first country to introduce NOTA.
- Bangladesh is the first Asian country to introduce NOTA.
- India is the 14th country to introduce NOTA in elections.
- NOTA was used first time in India in the 2013 state election.
- In India, NOTA was first counted in New Delhi.
- The symbol of NOTA was designed by the National Institute of design, Ahmedabad.
- The first time it was used was during the Assembly elections held in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Mizoram and Delhi.
- The option of NOTA in Rajya Sabha polls was introduced by the EC in 2014

नोटा एक नकारात्मक वोट है जिसे कोई भी नागरिक तब डाल सकता है जब वह किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट न हो।

नोटा को 27 सितंबर 2013 को वैध कर दिया गया।

नोटा पेश करने वाला फ्रांस पहला देश है।

नोटा लागू करने वाला बांग्लादेश पहला एशियाई देश है।

भारत चुनाव में नोटा पेश करने वाला 14वां देश है।

भारत में पहली बार 2013 के राज्य चुनाव में नोटा का इस्तेमाल किया गया था।

भारत में नोटा की गिनती सबसे पहले नई दिल्ली में हुई थी।

नोटा का प्रतीक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया था।

पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था।

राज्यसभा चुनावों में NOTA का विकल्प चुनाव आयोग द्वारा 2014 में पेश किया गया था।

Q54. The ideals of Liberty, Equality, and Fraternity (contained in the Preamble of the Constitution of India) are borrowed from the constitution of which country?

स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श (भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित) किस देश के संविधान से लिए गए हैं?

- A. Australia /ऑस्ट्रेलिया
- B. Canada /कनाडा
- C. Germany /जर्मनी
- D. France /फ्रांस

Sol-

The Indian Preamble borrowed its ideals of Liberty, Equality, and Fraternity from the French Constitution. The Indian state came to be recognized as the 'Republic of India' in the lineage of the Constitution of France.

भारतीय प्रस्तावना ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने आदर्शों को फ्रांसीसी संविधान से उधार लिया था। भारतीय राज्य को फ्रांस के संविधान के वंश में 'भारत गणराज्य' के रूप में मान्यता दी जाने लगी।

Q55. Arms Forces Tribunal is established in which year?

आर्म्स फोर्स ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई है?

- A. 2008
- B. 2009
- C. 2012
- D. 2013

Sol-

Formed - 8 August 2009

Jurisdiction - Government of India

Headquarters - New Delhi, India

Minister responsible - Rajnath Singh, Minister of Defence

Agency executive - Rajendra Menon, Chairperson

Parent department - Ministry of Defence

गठित - 8 अगस्त 2009

क्षेत्राधिकार - भारत सरकार

मुख्यालय - नई दिल्ली, भारत

जिम्मेदार मंत्री - राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

एजेंसी कार्यकारी - राजेंद्र मेनन, अध्यक्ष

मूल विभाग - रक्षा मंत्रालय

Q56. Which of the following power does not belong to Prime Minister?

निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रधान मंत्री से संबंधित नहीं है?

- A. Advices President to appoint other Ministers /राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह
- B. Preside over the meeting of council of Ministers /मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता
- C. Guides, Directs, controls and coordinates all ministries /सभी मंत्रालयों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है
- D. Appoints other ministers /अन्य मंत्रियों की नियुक्ति

Sol-

The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।

Q57. The Supreme Court has declared access to the Internet a fundamental right under Article of the Indian Constitution.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है।

- A. 21
- B. 14
- C. 17
- D. 19

Sol-

The Supreme Court has declared access to the internet a fundamental right under Article 19 of the Indian Constitution.

Article 19 - Freedom of Speech

Article 14 - Equality before the law or equal protection of the laws

Article 21 - Liberty to live life

Article 17 - Abolition of untouchability

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है।

अनुच्छेद 19 - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण

अनुच्छेद 21 - जीवन जीने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का उन्मूलन

Q58. In which of the following years was the Congress Socialist Party (CSP) founded?

निम्नलिखित में से किस वर्ष में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना की गई थी?

- A. 1943
- B. 1914
- C. 1924
- D. 1934

Sol-

JP Narayan convened a meeting in Patna on 17 May 1934, which founded the Bihar Congress Socialist Party. He was a Gandhian Socialist. Narayan became general secretary of the party and Acharya Narendra Deva became president.

जेपी नारायण ने 17 मई 1934 को पटना में एक बैठक बुलाई, जिसने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। वे गांधीवादी समाजवादी थे। नारायण पार्टी के महासचिव बने और आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष बने।

Q59. Chief Justice of India can be removed from his office by the President on the recommendation of the

भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किसकी सिफारिश पर उनके पद से हटाया जा सकता है?

- A. Prime Minister /प्रधान मंत्री
- B. Vice President /उपाध्यक्ष
- C. Election Commission /चुनाव आयोग
- D. Parliament /संसद

Sol-

- He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament.
- The chief justice of the Supreme Court of India, is the chief judge of the Supreme Court of India as well as the highest-ranking officer of the Indian federal judiciary.
- The Constitution of India grants power to the president of India to appoint, in consultation with the outgoing chief justice, the next chief justice, who will serve until they reach the age of sixty-five or are removed by impeachment. As per convention, the name suggested by the incumbent chief justice is almost always the next senior most judge in the Supreme Court.
- Article 124(4) of Constitution of India lays down the procedure for removal of a judge of Supreme Court which is applicable to chief justices as well.
- The 48th and present chief justice is N. V. Ramana.

उन्हें संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ भारतीय संघीय न्यायपालिका के सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं।

भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति को निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, अगले मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, जो तब तक सेवा करेंगे जब तक वे पैंसठ वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाते हैं। परंपरा के अनुसार, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुझाया गया नाम लगभग हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 124(4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताता है जो मुख्य न्यायाधीशों पर भी लागू होता है। 48वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमण हैं।

Q60. Part VIII of the Constitution of India deals with

भारत के संविधान का भाग VIII संबंधित है

- A. Panchayats /पंचायतों
- B. States /राज्य अमेरिका
- C. Union Territories /केंद्र शासित प्रदेश
- D. Municipalities /नगर पालिकाओं

Sol-

Union Territories are covered under Part VIII of the Constitution of India. In Part VIII of the Constitution of India Articles 239 to 242 deal with the Union Territories.

केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग VIII के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग VIII में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

Q61. Name the first judge of the Supreme Court, against which the proposal of impeachment was presented in the Parliament of independent India.

सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए, जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था।

- A. Justice Ramswami /न्यायमूर्ति रामस्वामी
- B. Justice Mahajan /न्यायमूर्ति महाजन
- C. Justice Veerswamy /न्यायमूर्ति वीरस्वामी
- D. Justice Subba Rao /जस्टिस सुब्बा राव

Sol-

Veeraswami Ramaswami was a judge of the Supreme Court of India and the first judge against whom removal proceedings were initiated in independent India.

In 1993, the motion was brought up in Lok Sabha, but it failed to secure the required two-thirds majority.

Justice Ramaswami was caught in a controversy for spending extravagantly on his official residence during his tenure as Chief Justice of Punjab and Haryana during 1990. The Supreme Court Bar Association even passed a resolution calling for his impeachment. R

1993 में, प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था, लेकिन यह आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा।

वीरस्वामी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई थी।

न्यायमूर्ति रामास्वामी 1990 के दौरान पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक आवास पर फालतू खर्च करने के लिए एक विवाद में फंस गए थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके महाभियोग का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया था।

Q62. The maximum number of nominated members to Lok Sabha is

लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

Sol-

Lok Sabha can have 552 members at maximum, out of which 530 are elected from the states, 2 are nominated by the President, and 20 are from 8 Union Territories.

लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 530 राज्यों से चुने जाते हैं, 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 20, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं।

Q63. Who decides on the issue related to the disqualification of a Member of Lok Sabha under tenth schedule?

दसवीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है?

- A. Prime Minister /प्रधान मंत्री
- B. President /राष्ट्रपति
- C. Vice President /उपराष्ट्रपति
- D. Speaker /वक्ता

Sol-

The Speaker decides on the issue related to the disqualification of a Member of Lok Sabha under Tenth Schedule.

The 10th Schedule of the Indian Constitution is also known as Anti-Defection Law.

It was inserted by the 52nd Amendment in 1985.

लोकसभा अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता है।

भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को दलबदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।

इसे 1985 में 52वें संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था।

Q64. What is the term of the elected representatives of a gram Panchayat?

ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है?

- A. 5 years /वर्ष
- B. 2 years /वर्ष
- C. 4 years /वर्ष
- D. 3 years /वर्ष

Sol-

The Panchayat is chaired by the president of the village, known as a Sarpanch. The term of the elected representatives is five years.

पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसे सरपंच कहा जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।

Q65. The Constitution of India was amended for the first time in which year?

भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था?

- A. 1961
- B. 1960
- C. 1951
- D. 1954

Sol-

The Constitution of India was amended for the first time on 10th May 1951.

The Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution (First Amendment) Bill, 1951 was enacted as the Constitution (First Amendment) Act, 1951.

The first amendment added Article 15(4) and Article 19(6) and also brought changes in the right to property in pursuance after the decision of Supreme Court regarding Fundamental Right of the Citizens.

भारत के संविधान में पहली बार 10 मई 1951 को संशोधन किया गया था।

संविधान (प्रथम संशोधन) विधेयक, 1951 से संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 के रूप में अधिनियमित किया गया था।

पहले संशोधन ने अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 19(6) को जोड़ा और नागरिकों के मौलिक अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन भी लाया।

Q66. Whose recommendation is mandatory to impeach the President of India from his office before the completion of his/her term?

भारत के राष्ट्रपति पर उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके कार्यालय से महाभियोग चलाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है?

- A. The Prime Minister /प्रधानमंत्री
- B. The Speaker of the Lok Sabha /लोकसभा अध्यक्ष
- C. The Chief Justice of India /भारत के मुख्य न्यायाधीश
- D. The two houses of the parliament /संसद के दो सदन

Sol-

The recommendation of the houses of the parliament is mandatory to impeach the President of India from his office before the completion of his/her term.

संसद के सदनों की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनके कार्यालय से महाभियोग चलाने के लिए अनिवार्य है।

Q67. Who administers the oath of the President of India?

भारत के राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दलाई जाती है ?

- A. Governor General of India /भारत के गवर्नर जनरल
- B. Chief Justice of India /भारत के मुख्य न्यायाधीश**
- C. Prime Minister of India /भारत के प्रधानमंत्री
- D. Vice President of India /भारत के उपराष्ट्रपति

Sol-

The Chief Justice of India administers the oath of the office to the President. In case the Chief Justice of India is unavailable the oath shall be administered by the senior most judge of the Supreme Court of India.

भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपलब्ध होने की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दलाई जाएगी।

Q68. Who is the custodian of Contingency Fund of India?

भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है?

- A. The Prime Minister /प्रधानमंत्री
- B. Judge of Supreme Court /सुप्रीम कोर्ट के जज
- C. The President /राष्ट्रपति**
- D. The Finance Minister /वित्त मंत्री

Sol-

The Contingency Fund of India established under Article 267 (1) of the Constitution is in the nature of an imprest (money maintained for a specific purpose) which is placed at the disposal of the President to enable him/her to make advances to meet urgent unforeseen expenditure, pending authorization by the Parliament.

Accordingly, Parliament enacted the contingency fund of India Act 1950. The fund is held by the Finance Secretary (Department of Economic Affairs) on behalf of the President of India and it can be operated by executive action.

संविधान के अनुच्छेद 267 (1) के तहत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय (एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखी गई धनराशि) की प्रकृति में है, जिसे राष्ट्रपति के निपटान में रखा जाता है ताकि वह तत्काल मिलने के लिए अग्रिम कर सकें। अप्रत्याशित व्यय, संसद द्वारा लंबित प्राधिकरण।

तदनुसार, संसद ने भारत अधिनियम 1950 की आकस्मिक निधि अधिनियमित की। यह निधि भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव (आर्थिक मामलों के विभाग) के पास है और इसे कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित किया जा सकता है।

Q69. Which of the following is not a fundamental duty?

निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है?

- A. To abide by constitution and respect the National Flag /संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना
- B. To promote harmony and brotherhood /सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए
- C. To uphold and protect the sovereignty /संप्रभुता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए
- D. Abolition of titles except military and academic /सैन्य और अकादमिक को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन**

Sol-

S.No	11 Fundamental Duties
1.	Abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem
2.	Cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom
3.	Uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
4.	Defend the country and render national service when called upon to do so
5.	Promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women
6.	Value and preserve the rich heritage of the country's composite culture
7.	Protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures
8.	Develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform
9.	Safeguard public property and to abjure violence
10.	Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement
11.	Provide opportunities for education to his child or ward between the age of six and fourteen years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002

Q70. There are total seats (Rajya Sabha constituency) in Punjab.

ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕੁਲ ਸੀਟੋਂ (ਰਾਜਯਸਭਾ ਨਿਰਵਾਚਨ ਕੇਤਰ) ਹੈਂ।

- A. 7
- B. 1
- C. 18
- D. 10

Sol-

There are total 20 Member Parliament from Punjab. 13 in Lok Sabha and 7 in Rajya Sabha.

ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕੁਲ 20 ਸਦਸ਼ੀਯ ਸੰਸਦ ਹੈਂ। ਲੋਕਸਭਾ ਮੇਂ 13 ਔਰ ਰਾਜਯਸਭਾ ਮੇਂ 7.

Q71. Constituent Assembly of India was founded in the year

ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਸ਼ ਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਥੀ

- A. 1940
- B. 1946
- C. 1947
- D. 1950

Sol-

The Constituent Assembly of India was elected to frame the Constitution of India. It was elected by the 'Provincial Assembly'. Following India's independence from British Government in 1947, its members served as the nation's first Parliament.

Initially, the number of members was 389. After partition, some of the members went to Pakistan and the number came down to 299. Out of this, 229 were from the British provinces and 70 were nominated from the princely states.

Dr. Sachchidananda Sinha was the first temporary chairman of the Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President and its Vice President was Harendra Coomar Mookerjee. BN Rau was the constitutional advisor. भारत की संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुना गया था। इसे 'प्रांतीय सभा' द्वारा चुना गया था। 1947 में ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता के बाद, इसके सदस्यों ने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया।

प्रारंभ में, सदस्यों की संख्या 389 थी। विभाजन के बाद, कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संख्या घटकर 299 रह गई। इसमें से 229 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 70 रियासतों से नामित किए गए थे।

डॉ सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और इसके उपाध्यक्ष हरेन्द्र कुमार मुखर्जी थे। बीएन राव संवैधानिक सलाहकार थे।

Q72. In which year was All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) founded?

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

- A. 1949
- B. 1999
- C. 1972
- D. 1997

Sol –

Party	Abbr. ⇄	Political position ⇄	Ideology ⇄	Founded ⇄	National status accorded ⇄	Leader(s) ⇄
All India Trinamool Congress English: All India Grassroots Congress	AITC	Centre-left	Secularism Populism Progressivism	1 January 1998 (24 years ago)	2 September 2016	Mamata Banerjee (Chairperson)
Bahujan Samaj Party English: Majority Community Party	BSP	Centre-left	Social equality Social justice Secularism Self-respect Human Rights	14 April 1984 (37 years ago)		Mayawati (President)
Bharatiya Janata Party English: Indian People's Party	BJP	Right-wing	Hindutva Integral humanism Conservatism Social conservatism Right-wing populism	6 April 1980 (41 years ago)		J. P. Nadda (President)
Communist Party of India	CPI	Left-wing	Communism Marxism–Leninism	26 December 1925 (96 years ago)		D. Raja (General Secretary)
Communist Party of India (Marxist)	CPI(M)	Left-wing	Communism Marxism–Leninism	7 November 1964 (57 years ago)		Sitaram Yechury (General Secretary)
Indian National Congress	INC	centre-left	Big tent Social democracy Democratic socialism Liberal nationalism Secularism Progressivism	28 December 1885 (136 years ago)		Sonia Gandhi (President)
Nationalist Congress Party	NCP	centre-left	Liberalism Gandhism	10 June 1999 (22 years ago)		Sharad Pawar (President)
National People's Party	NPP	Centre	Regionalism Ethnocentrism	6 January 2013 (9 years ago)	7 June 2019	Conrad Sangma (President)

Q73. "Forests" is listed in the list given in the Seventh Schedule in the Constitution of India.

वन" भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है।

- A. Union /संघ
- B. State /राज्य

C. Global /वैश्विक

D. Concurrent /समवर्ती

Sol-

Forests are listed in concurrent list. This list covers 52 items including Criminal Law, IPC, Criminal Procedure, Marriage & divorce, Bankruptcy & Insolvency, Forests, Education.

वन समवर्ती सूची में सूचीबद्ध हैं। इस सूची में आपराधिक कानून, आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, दिवालियापन और दिवाला, वन, शिक्षा सहित 52 आइटम शामिल हैं।

Q74. Which parliamentary committee in India is normally chaired by a prominent member of the opposition?

भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता आम तौर पर विपक्ष के एक प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है?

A. Committee on Government Assurances /सरकारी आश्वासनों पर समिति

B. Estimates Committee /प्राक्कलन समिति

C. Privileges Committee /विशेषाधिकार समिति

D. Public Accounts Committee /लोक लेखा समिति

Sol-

Public Accounts Committee is the oldest Parliamentary Committee. It helps Parliament in strengthening the financial control over executive. It consists of 22 members, out of which 15 are from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha.

लोक लेखा समिति सबसे पुरानी संसदीय समिति है। यह कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने में संसद की सहायता करता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं।

Q75. The President can dismiss a member of the Council of Ministers

राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है

A. with the consent of the Speaker /अध्यक्ष की सहमति से

B. only under emergency conditions /केवल आपातकालीन परिस्थितियों में

C. on the recommendation of the Prime Minister /प्रधानमंत्री की सिफारिश पर

D. on his own /अपने दम पर

Sol-

Article 74 of Indian constitution provides for the Council of Ministers to aid and advise President. The President appoints the council of ministers and distributes portfolios among them on the advice of the Prime Minister. On his recommendation, the President can dismiss any minister from the council of ministers.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके बीच विभागों का वितरण करता है। उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकता है।

Q76. Right to Constitutional Remedies comes under

संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है

A. Legal rights /कानूनी अधिकार

B. Fundamental rights /मौलिक अधिकार

C. Human rights /मानव अधिकार

D. Natural rights /प्राकृतिक अधिकार

Sol-

This right comes under article 32 for Supreme court and article 226 for the high court.

It is known as the right to constitutional remedies. In this right, the Supreme court, as well as high court, is given the power to instill the fundamental rights.

Furthermore, the power can be issued by local courts also to extend the rights.

Although, there is one act which comes under the military law known as the court-martial which is exempted from this right.

Also, it is important to note that article 32 can be invoked only to get remedies related to fundamental rights. Thus, it cannot be there for any legal or constitutional right. For these rights, there are different laws available.

यह अधिकार उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है।

इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। इस अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी मौलिक अधिकारों को स्थापित करने की शक्ति दी गई है।

इसके अलावा, अधिकारों का विस्तार करने के लिए स्थानीय अदालतों द्वारा भी शक्ति जारी की जा सकती है।

हालांकि, एक अधिनियम है जो सैन्य कानून के तहत आता है जिसे कोर्ट-मार्शल के रूप में जाना जाता है जिसे इस अधिकार से छूट दी गई है।

साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 32 को केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित उपचार प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, यह किसी भी कानूनी या संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं हो सकता है। इन अधिकारों के लिए अलग-अलग कानून उपलब्ध हैं।

Q77. Who among the following advises the Union government on legal matters?

निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है?

- A. Chief Justice of India /भारत के मुख्य न्यायाधीश
- B. Comptroller and Auditor General of India /भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- C. **Attorney General /महान्यायवादी**
- D. Advocate General /महाधिवक्ता

Sol-

The Attorney General for India is the Indian government's chief legal advisor, and is its principal Advocate before the Supreme Court of India.

They are appointed by the President of India on the advice of the Union Cabinet under Article 76(1) of the Constitution and hold office during the pleasure of the President.

भारत के लिए महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसका प्रमुख अधिवक्ता है।

वे संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।

Q78. Who is also known as Guardian of Public Purse?

सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है?

- A. NITI Aayog /नीति आयोग
- B. **Comptroller and Auditor General of India /भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक**
- C. Attorney General /महान्यायवादी
- D. Chief Information Commissioner /मुख्य सूचना आयुक्त

Sol-

CAG of India, or also the "Guardian of the Public Purse", is vested with the responsibility of inspecting and auditing all the expenditure of both the Central and the State Governments as well as of those organisations or the bodies which the government significantly funds.

भारत के सीएजी, या "सार्वजनिक पर्स के संरक्षक", को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ-साथ उन संगठनों या निकायों के सभी खर्चों के निरीक्षण और लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी निहित है, जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण रूप से निधि देती है।

Q79. What is the tenure of Comptroller and Auditor General of India?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है?

- A. 3 Years /वर्ष
- B. 6 Years /वर्ष**
- C. 4 Years /वर्ष
- D. 5 Years /वर्ष

Sol-

Nominator	Prime Minister of India
Appointer	President of India
Term length	6 yrs or up to 65 yrs of age (whichever is earlier)

Q80. Union Public Service commission is a _____ body.

संघ लोक सेवा आयोग एक _____ निकाय है।

- A. Constitutional /संवैधानिक**
- B. Statutory /वैधानिक
- C. Regulatory /नियामक
- D. Extra Constitutional /अतिरिक्त संवैधानिक

Sol-

The UPSC is a constitutional body.

The commission's approval is granted by the Constitution of India as mentioned in the articles 315 to 323 of Part XIV of the constitution titled as Services under the Union and the States for public service commission for the union and for each state.

यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है।

आयोग की स्वीकृति भारत के संविधान द्वारा दी गई है जैसा कि संविधान के भाग XIV के अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लिखित है, जिसका शीर्षक संघ और राज्यों के तहत संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग के लिए सेवाएं है।

Q81. When was the first Central Legislative Assembly constituted?

पहली केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था?

- A. 1922
- B. 1923
- C. 1921**
- D. 1920

Sol-

- The Central Legislative Assembly was the lower house of the Imperial Legislative Council, the legislature of British India.
- It was created by the Government of India Act 1919, implementing the Montagu–Chelmsford Reforms.
- It was also sometimes called the Indian Legislative Assembly and the Imperial Legislative Assembly.

- The Council of State was the upper house of the legislature for India.
- The Assembly had 145 members who were either nominated or indirectly elected from the provinces.
- A new "Council House" was conceived in 1919 as the seat of the future Legislative Assembly, the Council of State, and the Chamber of Princes.
- The foundation stone was laid on 12 February 1921 and the building was opened on 18 January 1927 by Lord Irwin, the Viceroy and Governor-General.
- The Council House later changed its name to Parliament House, or Sansad Bhavan, and is the present-day home of the Parliament of India.
- The Assembly, the Council of State, and the Chamber of Princes were officially opened in 1921 by King George V's uncle, the Duke of Connaught and Strathearn
- The Government of India Act 1935 introduced further reforms.
- The Assembly continued as the lower chamber of a central Indian parliament based in Delhi, with two chambers, both containing elected and appointed members.
- The Assembly increased in size to 250 seats for members elected by the constituencies of British India, plus a further 125 seats for the Indian Princely states. However, elections for the reformed legislature never took place.

केंद्रीय विधान सभा, ब्रिटिश भारत की विधायिका, शाही विधान परिषद का निचला सदन था।

यह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा बनाया गया था, जो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करता है।

इसे कभी-कभी भारतीय विधान सभा और शाही विधान सभा भी कहा जाता था।

राज्य परिषद भारत के लिए विधायिका का ऊपरी सदन था।

विधानसभा में 145 सदस्य थे जो या तो मनोनीत थे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों से चुने गए थे।

1919 में एक नए "काउंसिल हाउस" की कल्पना भविष्य की विधान सभा, राज्य परिषद और राजकुमारों के चैंबर की सीट के रूप में की गई थी।

12 फरवरी 1921 को आधारशिला रखी गई थी और भवन 18 जनवरी 1927 को वाइसराय और गवर्नर-जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा खोला गया था।

काउंसिल हाउस ने बाद में इसका नाम बदलकर संसद भवन, या संसद भवन कर दिया, और यह भारत की संसद का वर्तमान घर है।

1921 में किंग जॉर्ज पंचम के चाचा, ड्यूक ऑफ कनॉट एंड स्ट्रेथर्न द्वारा असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट और चैंबर ऑफ प्रिंसेस को आधिकारिक तौर पर खोला गया था।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने और सुधार पेश किए।

विधानसभा दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जारी रही, जिसमें दो कक्ष थे, दोनों में निर्वाचित और नियुक्त सदस्य थे।

ब्रिटिश भारत के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुने गए सदस्यों के लिए विधानसभा आकार में 250 सीटों तक बढ़ गई, साथ ही भारतीय रियासतों के लिए और 125 सीटें। हालांकि, सुधारित विधायिका के लिए चुनाव कभी नहीं हुए।

Q82. The method of amending the Constitution by popular veto is found in:

लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है:

- A. Britain /ब्रिटेन
- B. Switzerland /स्विट्जरलैंड
- C. Russia/रूस
- D. India /इंडिया

Sol-

When a bill is introduced in the Parliament, Parliament can pass the bill and before the bill becomes an act, it has to be presented to the Indian President for his approval.

It is up to the President of India to either reject the bill, return the bill or withhold his/her assent to the bill.

The choice of the President over the bill is called the veto power.

Veto Power of the President of India is guided by Article 111 of the Indian Constitution

जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है, तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक के अधिनियम बनने से पहले, इसे भारतीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होता है।

यह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह या तो बिल को अस्वीकार कर दे, बिल को वापस कर दे या बिल पर अपनी सहमति रोक दे। विधेयक पर राष्ट्रपति के चुनाव को वीटो पावर कहा जाता है।

भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है

Types of Veto		
Absolute Veto	Suspensive Veto	Pocket Veto
The power of the President to withhold the assent to the bill is termed as his absolute veto	The power of the President to return the bill to the Parliament with or without consideration is called suspensive veto	The power of the President to not act upon the bill is termed as a pocket veto

Q83. In which year Budget was presented for the first time?

पहली बार बजट किस वर्ष पेश किया गया था?

- A. 1885
- B. 1869
- C. 1857
- D. 1950

Sol-

The first Indian Budget was presented by **James Wilson** on February 18, 1869.

Wilson, whose designation was Finance Member of the India Council that advised the Indian Viceroy, was also the founder of The Economist and described by Karl Marx as an "economical mandarin of high standing".

But he was also a largely selftaught man who had worked in his family occupation making and selling hats, before becoming a scholar and a writer largely based on his brilliance and knowledge of economics and commerce.

पहला भारतीय बजट 18 फरवरी, 1869 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

विल्सन, जिसका पद भारतीय वायसराय को सलाह देने वाली भारतीय परिषद का वित्त सदस्य था, द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे और कार्ल मार्क्स द्वारा "उच्च स्तर के किराया मंदारिन" के रूप में वर्णित किया गया था।

लेकिन वह एक बड़े पैमाने पर आत्म-सिखाया हुआ व्यक्ति भी था, जिसने अपने परिवार के व्यवसाय में टोपी बनाने और बेचने का काम किया था, एक विद्वान और लेखक बनने से पहले काफी हद तक उनकी प्रतिभा और अर्थशास्त्र और वाणिज्य के ज्ञान पर आधारित था।

Q884. The maximum strength of the Select Committee of the Lok Sabha is

लोकसभा की प्रवर समिति की अधिकतम शक्ति है

- A. 10 members/सदस्य
- B. 5 members /सदस्य
- C. 15 members /सदस्य
- D. Not fixed and varies from Committee to Committee /तय नहीं है और समिति से समिति में भिन्न होता है

Sol-

Parliamentary Committee means a Committee which is appointed or elected by the House or nominated by the Speaker and which works under the direction of the Speaker and presents its report to the House or to the Speaker and the Secretariat for which is provided by the Lok Sabha Secretariat.

By their nature, Parliamentary Committees are of two kinds: Standing Committees and Ad hoc Committees.

Standing Committees are permanent and regular committees which are constituted from time to time in pursuance of the provisions of an Act of Parliament or Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. The work of these Committees is of continuous nature. The Financial Committees, DRSCs and some other Committees come under the category of Standing Committees.

Ad hoc Committees are appointed for a specific purpose and they cease to exist when they finish the task assigned to them and submit a report. The principal Ad hoc Committees are the Select and Joint Committees on Bills. Railway Convention Committee, Joint Committee on Food Management in Parliament House Complex etc also come under the category of ad hoc Committees.

Departmentally Related Standing Committees (DRSCs)

There are 24 Departmentally Related Standing Committees covering under their jurisdiction all the Ministries/ Departments of the Government of India. Each of these Committees consists of 31 Members - 21 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha to be nominated by the Speaker, Lok Sabha and the Chairman, Rajya Sabha, respectively. The term of Office of these Committees does not exceed one year.

संसदीय समिति का अर्थ है एक समिति जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नामित की जाती है और जो अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती है और सदन या अध्यक्ष और सचिवालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसके लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है .

अपने स्वभाव से, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां।

स्थायी समितियाँ स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं जिनका गठन समय-समय पर संसद के एक अधिनियम या लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य निरंतर प्रकृति का है। वित्तीय समितियां, डीआरएससी और कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी में आती हैं।

तदर्थ समितियों को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है और जब वे उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करते हैं और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां हैं। रेलवे कन्वेंशन कमेटी, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि भी तदर्थ समितियों की श्रेणी में आते हैं।

विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs)

विभागीय रूप से संबंधित 24 स्थायी समितियां शामिल हैं

उनके अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग। इन समितियों में से प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं - 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से क्रमशः अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। इनमें से कार्यालय की अवधि समितियां एक वर्ष से अधिक नहीं होती हैं।

A. Financial Committees

Sl. No.	Name of Committee	No. of Members	Tenure	Members nominated or elected.
1.	Estimates Committee	30	1 year	Elected by the Lok Sabha
2.	Public Accounts Committee	22(15LS+7RS)	1 year	Elected by the two House(s).
3.	Committee on Public Undertakings	22(15LS+7RS)	1 year	Elected by the two House(s).

Q85. Grants-in-aid are provided to such states as are in need of assistance by the
सहायता अनुदान ऐसे राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है

- A. Union Parliament /केंद्रीय संसद
- B. President /राष्ट्रपति
- C. Finance Commission /वित्त आयोग
- D. RBI /भारतीय रिजर्व बैंक

Q86. The Indian Administrative Service and the Indian Police Service have been created by the
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा किसके द्वारा बनाई गई है?

- A. Home Ministry /गृह मंत्रालय
- B. Union Public Service Commission /संघ लोक सेवा आयोग
- C. Parliament /संसद
- D. Supreme Court of India /भारत का सर्वोच्च न्यायालय

Sol-

The Indian Administrative Service and The Indian Police Service are deemed to be constituted by the Parliament in terms of Article 312 of the Constitution.

After the promulgation of the Constitution, a new All India Service, namely, The Indian Forest Service, was created in 1966.

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद द्वारा गठित माना जाता है। संविधान की घोषणा के बाद, 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा, भारतीय वन सेवा, का गठन किया गया।

Q87. The Third Schedule of the Constitution details
संविधान की तीसरी अनुसूची का विवरण

- A. Allocation of seats in the Rajya Sabha /राज्यसभा में सीटों का आवंटन
- B. The list of languages /भाषाओं की सूची
- C. Forms of oaths or affirmations /शपथ या प्रतिज्ञान के रूप
- D. The States and the Union Territories of India/भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

Sol-

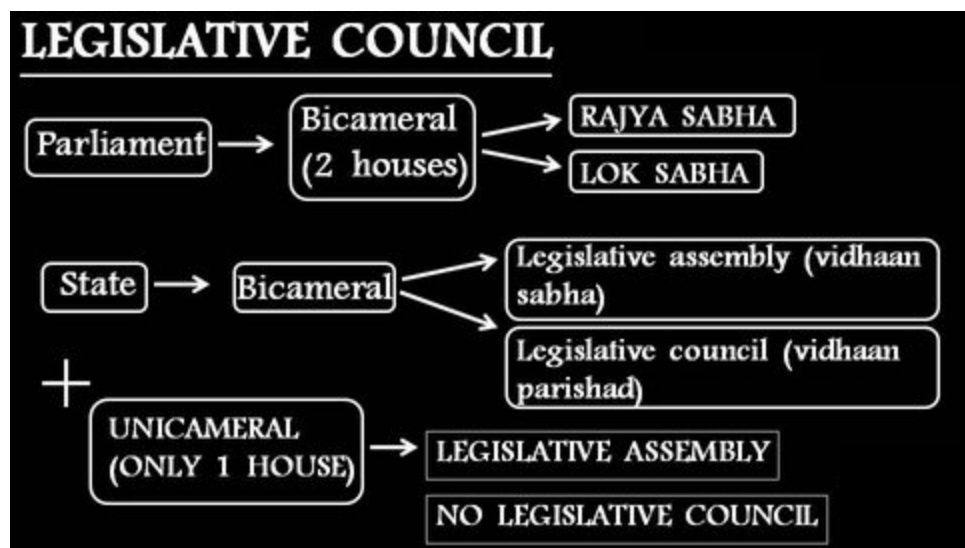
Schedules 1 to 12
First schedule contains the list of states and union territories and their territories
Second schedule contains provisions as to the President, Governors of States, Speaker and the Deputy Speaker of the House of the People and the Chairman and the Deputy Chairman of the Council of States and the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State, the Judges of the Supreme Court and of the High Courts and the Comptroller and Auditor-General of India the list of states and union territories and their territories
Third Schedule contains the Forms of Oaths or Affirmations.
Fourth Schedule contains provisions as to the allocation of seats in the Council of States.
Fifth Schedule contains provisions as to the Administration and Control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes.
Sixth Schedule contains provisions as to the Administration of Tribal Areas in the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.
Seventh Schedule contains the Union list, State list and the concurrent list.
Eighth Schedule contains the list of recognised languages.
Ninth Schedule contains provisions as to validation of certain Acts and Regulations.
Tenth Schedule contains provisions as to disqualification on ground of defection.
Eleventh Schedule contains the powers, authority and responsibilities of Panchayats.
Twelfth Schedule contains the powers, authority and responsibilities of Municipalities.

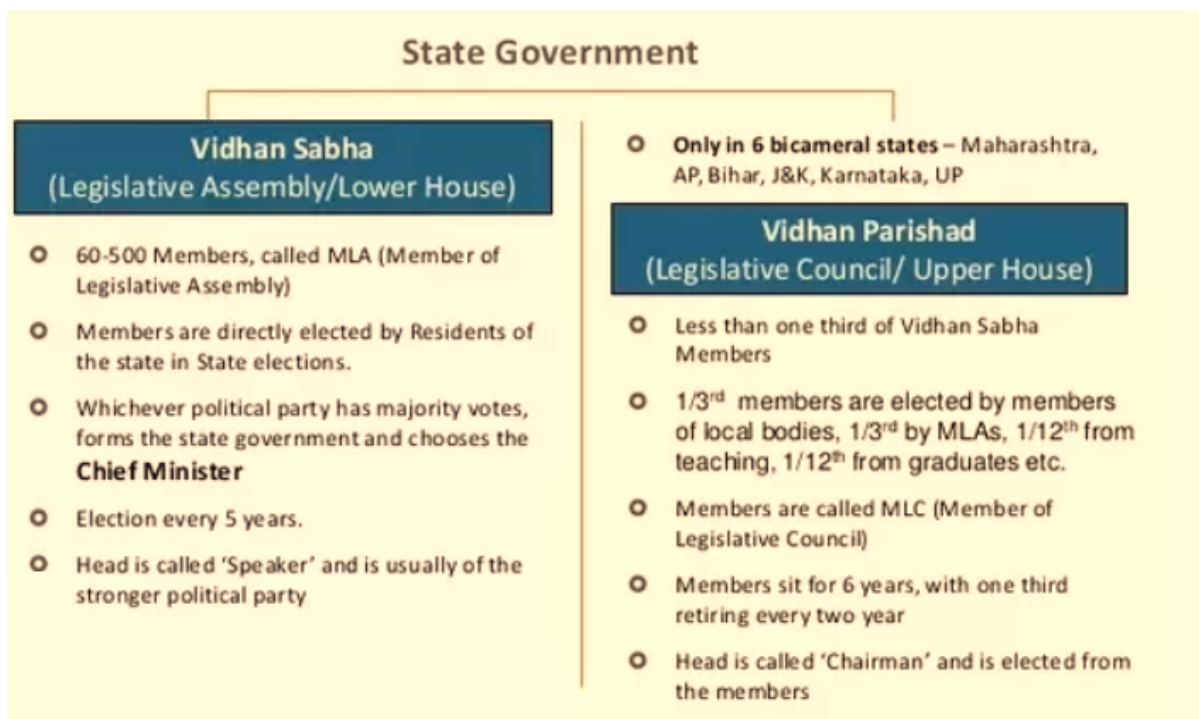
Q88. The Chief Minister remains in power as long as he enjoys the confidence of the

मुख्यमंत्री सत्ता में तब तक बना रहता है जब तक कि वह किसका विश्वास प्राप्त करता है

- A. Prime Minister/प्रधान मंत्री
- B. Governor/राज्यपाल
- C. State Legislative Assembly /राज्य विधान सभा
- D. People of the State /राज्य के लोग

Sol-





Q89. During the temporary absence of a Governor the _____ is appointed to officiate as Governor.

राज्यपाल की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

- A. Chief Secretary /मुख्य सचिव
- B. Speaker of the State Assembly /राज्य विधानसभा अध्यक्ष
- C. Chairman of the State Legislative Council /राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष
- D. Chief Justice of the State High Court /राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश**

Q90. The Governor is the _____ of the Universities in the State.

राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का _____ होता है।

- A. Chancellor /चांसलर**
- B. Pro-Chancellor /प्रो- चांसलर
- C. Vice-Chancellor /कुलपति
- D. Chief Executive /मुख्य कार्यकारी

Sol-

In most cases, the Governor of the state is the ex-officio chancellor of the universities in that state.

While the Governor's powers and functions as the Chancellor are laid out in the statutes that govern the universities under a particular state government.

Central Universities:

Under the Central Universities Act, 2009, and other statutes, the President of India shall be the Visitor of a central university.

Chancellors are appointed by the President in his capacity as Visitor.

They are titular heads with their role limited to presiding over convocations in central universities.

The VCs too are appointed by the Visitor from panels of names picked by search and selection committees formed by the Union government.

ज्यादातर मामलों में, राज्य के राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर होते हैं। जबकि राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को कुलाधिपति के रूप में उन विधियों में निर्धारित किया जाता है जो एक विशेष राज्य सरकार के तहत विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय:

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और अन्य विधियों के तहत, भारत के राष्ट्रपति एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे। कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कुलाध्यक्ष के रूप में उनकी हैसियत से की जाती है। वे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करने तक सीमित अपनी भूमिका के साथ टाइटेनिक प्रमुख हैं। कुलपतियों को भी केंद्र सरकार द्वारा गठित खोज और चयन समितियों द्वारा चुने गए नामों के पैनल से विज़िटर द्वारा नियुक्त किया जाता है।

Q91. To ensure their impartiality, a retired Chief Justice of India or other Judges of the Supreme Court are debarred from practicing in any

उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को किसी भी व्यवसाय में अभ्यास करने से वंचित कर दिया जाता है।

- A. court other than the apex court /सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय
- B. court in India /भारत में अदालत**
- C. court other than State High Courts /राज्य उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य न्यायालय
- D. Criminal court /क्रिमिनल कोर्ट

Sol-

The Judiciary in India is single, integrated and independent.

Article 50 of the Constitution of India provides for the separation of judiciary from the executive.

To maintain the independence of the Supreme Court constitution of India prohibits the retired judges to plead or act in any court or before any authority within the territory of India.

भारत में न्यायपालिका एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान करता है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष याचना करने या कार्य करने से रोकता है।

Q92. Which among the following amendments of Constitution of India had accorded precedence to Directive Principles over Fundamental Rights?

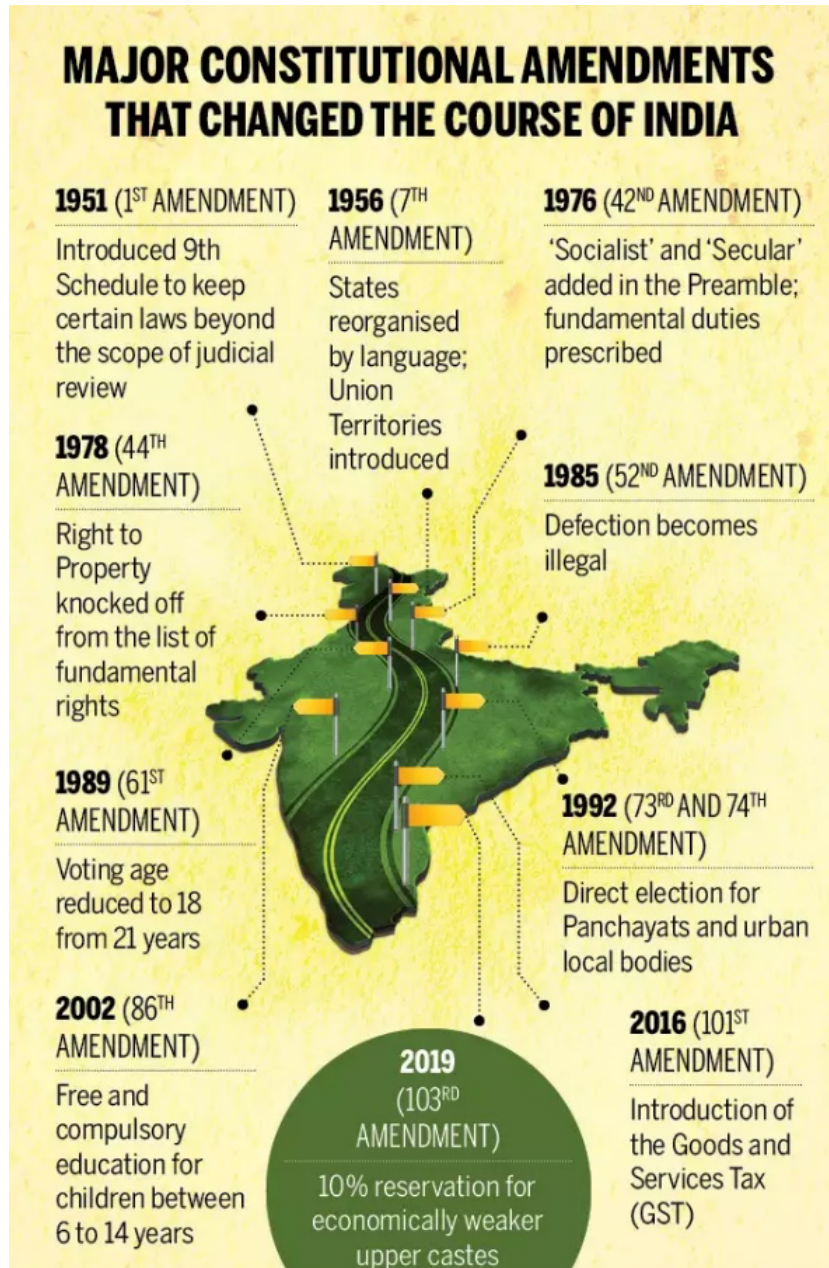
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी?

- A. 25th
- B. 42nd**
- C. 59th
- D. 44th

Sol-

42nd Amendment gave primacy to the Directive Principles, by stating that "no law implementing any of the Directive Principles could be declared unconstitutional on the grounds that it violated any of the Fundamental Rights".

42वें संशोधन ने निदेशक सिद्धांतों को प्रधानता देते हुए कहा कि "किसी भी निदेशक सिद्धांत को लागू करने वाले किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि यह किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है"।



Q93. Which of the following systems is also known as the Hare System?

निम्नलिखित में से किस प्रणाली को हरे प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है?

- A. Single transferable vote system /एकल संक्रमणीय मत प्रणाली
- B. List system /सूची प्रणाली
- C. Limited vote system /सीमित वोट प्रणाली
- D. Single non-transferable vote system /एकल अहस्तांतरणीय मत प्रणाली

Sol-

The Hare quota (also known as the simple quota) is a formula used under some forms of the Single Transferable Vote (STV) system and the largest remainder method of party-list proportional representation.

हरे कोटा (साधारण कोटा के रूप में भी जाना जाता है) एकल हस्तांतरणीय वोट (एसटीवी) प्रणाली के कुछ रूपों के तहत उपयोग किया जाने वाला एक सूत्र है और पार्टी-सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी शेष विधि है।

Q94. Who defeated Mrs Gandhi in the 1977 Lok Sabh elections?

1977 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती गांधी को किसने हराया था?

- A. Morarji Desai /मोरारजी देसाई
- B. Raj Narain /राज नारायण**
- C. Charan Singh /चरण सिंह
- D. JP Narayan /जेपी नारायण

Sol-

Narain joined with other opposition parties to form the Janata alliance to face Mrs. Gandhi's Congress party.

Narain once again stood against her from the Rae Bareilly constituency.

He defeated her with a margin of more than fifty thousand votes.

श्रीमती गांधी की कांग्रेस पार्टी का सामना करने के लिए जनता गठबंधन बनाने के लिए नारायण अन्य विपक्षी दलों के साथ शामिल हुए।

रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से नारायण एक बार फिर उनके खिलाफ खड़े हो गए।

उन्होंने उन्हें पचास हजार से अधिक मतों के अंतर से हराया।

Q95. Ms Sujatha Vaaant Manohar was the woman judge of the Supreme Court of India.

सुश्री सुजाता वंत मनोहर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश थीं।

- A. first /प्रथम
- B. second /दूसरा**
- C. third /तीसरा
- D. fourth /चौथी

Sol-

Sujata Vasant Manohar (born 28 August 1934) is a retired judge of the Supreme Court of India (retired in 1999) and a former member of the National Human Rights Commission of India.

सुजाता वसंत मनोहर (जन्म 28 अगस्त 1934) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (1999 में सेवानिवृत्त) और भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पूर्व सदस्य हैं।

Q96. Who acted as Prime Minister of India for 12 days on the death of Jawaharlal Nehru?

जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर 12 दिनों तक भारत के प्रधान मंत्री के रूप में किसने कार्य किया?

- A. Morarji Desai /मोरारजी देसाई
- B. Mrs Indira Gandhi /श्रीमती इंदिरा गांधी
- C. Gulzari Lal Nanda /गुलजारी लाल नंद**
- D. Lal Bahadur Shastri /लाल बहादुर शास्त्री

Sol-

Gulzarilal Nanda BR (4 July 1898 – 15 January 1998) was an Indian politician and economist who specialized in labour issues.

He was the Interim Prime Minister of India for two 13-day stints following the deaths of Jawaharlal Nehru in 1964 and Lal Bahadur Shastri in 1966 respectively.

Both his terms ended after the ruling Indian National Congress's parliamentary party elected a new prime minister. He was awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award, in 1997.

गुलजारीलाल नंदा बीआर (4 जुलाई 1898 - 15 जनवरी 1998) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, जो श्रम मुद्दों में विशेषज्ञता रखते थे। वह 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद दो 13 दिनों के कार्यकाल के लिए भारत के अंतरिम प्रधान मंत्री थे। सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय दल द्वारा एक नया प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद उनके दोनों कार्यकाल समाप्त हो गए। उन्हें 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।



Portrait of Nanda on a 1999 stamp of India

Interim Prime Minister of India	
In office	
11 January 1966 – 24 January 1966	
President	Sarvepalli Radhakrishnan
Preceded by	Lal Bahadur Shastri
Succeeded by	Indira Gandhi
In office	
27 May 1964 – 9 June 1964	
President	Sarvepalli Radhakrishnan
Preceded by	Jawaharlal Nehru
Succeeded by	Lal Bahadur Shastri

Q97. When the Union Council of Ministers tenders an advice to the President, he

जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, तो वह

- A. can refer it to the Supreme Court /इसे सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं
- B. can ignore it /इसे अनदेखा कर सकते हैं
- C. will be bound by it /इससे बंधे रहेंगे
- D. can reject it outright /इसे सिरे से खारिज कर सकते हैं

Sol-

Article 74 in The Constitution Of India - Council of Ministers to aid and advise President

भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 - राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

Q98. Under the 44th Amendment Act the President was deprived of the power to declare a

44वें संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को घोषित करने की शक्ति से वंचित कर दिया गया था

- A. Financial Emergency /वित्तीय आपातकाल
- B. Constitutional Emergency /संवैधानिक आपातकाल
- C. National Emergency on ground of "Internal Disturbance" /"आंतरिक अशांति" के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल
- D. War against our neighbours /हमारे पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध

Sol-

Officially issued by President Fakhruddin Ali Ahmed under Article 352 of the Constitution because of the prevailing "internal disturbance", the Emergency was in effect from 25 June 1975 until its withdrawal on January 1977. आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत प्रचलित "आंतरिक अशांति" के कारण जारी किया गया, आपातकाल 25 जून 1975 से जनवरी 1977 तक वापस लेने तक प्रभावी था।

Q99. The first National Emergency declared in October 1962 lasted till अक्टूबर 1962 में घोषित पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक चला?

- A. 1965
- B. 1966
- C. 1967
- D. 1968

Sol-

In the history of independent India, a state of emergency has been declared thrice.

The first instance was between 26 October 1962 to 10 January 1968 during the India-China war, when "the security of India" was declared as being "threatened by external aggression".

स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीन बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है।

पहला उदाहरण भारत-चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच था, जब "भारत की सुरक्षा" को "बाहरी आक्रमण से खतरा" घोषित किया गया था।

Q100. The Special Officer for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is appointed by the अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है

- A. Prime Minister/प्रधान मंत्री
- B. President /राष्ट्रपति
- C. Law Minister/कानून मंत्री
- D. Vice-President /उपराष्ट्रपति

Sol-

There shall be a Special Officer for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to be appointed by the President. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।